राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 36 अंक 8 नवम्बर 2015 मूल्य 5 रु. पृष्ठ 44

मुद्दों पर मंथन

छात्रा संसद में मंचासीन केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी के साथ अभाविप पदाधिकारी

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू तथा अभाविप के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर के छात्र नेता

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मण्डल

आशुतोष

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-23216298

ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com

वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली - 110007 से प्रकाशित एवं 102, एल. एस. सी., ऋषभ विहार मार्केट दिल्ली-92 से मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय

"छात्रशक्ति भवन"

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
संपादकीय	4
अखिल भारतीय जनजातीय छात्र–युवा संसद : रिपोर्ट	5
अखिल भारतीय छात्रा संसद : रिपोर्ट	7
पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद : रिपोर्ट	9
जनजातीय शिक्षा आयोग बनाने की उठी मांग	11
जनजातीय छात्र युवा संसद घोषणा पत्र	12
हर गांव में होगी स्पेशल महिला पुलिस अफसर – मेनका गांधी	14
सबके साथ पूर्वोत्तर का विकास – रिजिजू	18
'पूर्वोत्तर को जानो, भारत को जानो'	19
प्रो. केलकर युवा पुरस्कार इम्तियाज अली को	20
छात्र–युवा संसद झलकियां (फोटो)	21–24
साहित्य स्वहित के बीच पुरस्कार वापसी पर प्रश्न –अजय दुबे 'साथी'	25
वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरुरत – अभाविप	28
दिल्ली विश्वविद्यालय में अभाविप छात्रों ने किया प्रदर्शन	29
एक ओंकार सतनाम.. – आकाश कुमार राय	30
राष्ट्र का करना होगा पुनर्निर्माण – सुनील आंबेकर	32
बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अभाविप की महारैली	33
नई खिलाफत के खलीफा – अवनीश राजपूत	34
रोजगार परक शिक्षा नीति का हो निर्माण	36
सूर्य की उपासना का महापर्व 'छठ पूजा' – सुनील दुबे	37
केरल में बीफ उत्सव में परोसा गया गौमांस	39
फिर कामयाब हुआ अभाविप का संघर्ष	40
भुवनेश्वर में होगा अभाविप का 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन	42

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

गत एक, दो और तीन अक्तूबर को दिल्ली में आयोजित छात्र संसद ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सर्वस्पर्शी भूमिका का उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के राजनैतिक और शैक्षिक मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने में विफल रहे क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना, इसे अभाविप ने अपनी जिम्मेदारी समझा और राजधानी दिल्ली में उन क्षेत्र के युवाओं को एकत्र कर उन्हें अपनी समस्याओं को सम्बंधित विषयों के नीति नियंताओं के साथ साझा करने का अवसर प्रदान किया।

1 अक्तूबर को अखिल भारतीय जनजातीय युवा संसद, 2 अक्तूबर को अखिल भारतीय छात्रा संसद और तीन अक्तूबर को पूर्वोत्तर छात्र-नेता संसद का आयोजन किया गया। छात्राओं को तो विभिन्न संगठनों द्वारा किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत अवसर मिलता भी है, किन्तु जनजाति छात्रों और पूर्वोत्तर के छात्रों को राजधानी में बुलाने का विचार ही अनूठा था। विशेष रूप से पूरे पूर्वोत्तर से 52 छात्र एवं युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व दर्शाता है कि वे भी मुख्य धारा से जुड़ने और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान को आतुर हैं।

पूर्वोत्तर के आने वाले अनेक छात्र संगठन ऐसे भी हैं जिनके उद्देश्य अथवा कार्यप्रणाली परस्पर विरोधी अथवा एक-दूसरे के हितों के विपरीत भी है। लेकिन इस आयोजन से यह सिद्ध हुआ कि यदि उचित मंच मिले तो वे अपने छोटे हितों को छोड़ कर समूचे पूर्वोत्तर के समग्र विकास के महत्वाकांक्षी अभियान में जुट सकते हैं।

एक ओर शैक्षिक मुद्दे हैं तो दूसरी ओर समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश। देश के तमाम हिस्सों में बीफ फेस्टीवल के आयोजन के द्वारा बहुसंख्यक भावनाओं को अपमानित करने के कुत्सित प्रयासों में पिछले कुछ समय से तेजी आयी है। भोजन की थाली को राजनैतिक मंसूबों और साम्प्रदायिक उन्माद के विनाशकारी परिपाक से विषैला किया जा रहा है।

अधिकांश जगहों पर गैर हिन्दू समुदाय को आगे कर होने वाले इन आयोजनों के पीछे आमतौर पर वामपंथी अराजक तत्व नजर आते हैं। सदैव से देश को विभाजन और अराजकता की ओर धकेलने के प्रयासों में लगे यह तत्व समाज द्वारा किनारे कर दिये जाने के बाद साम्प्रदायिकता को हवा देकर अपनी वापसी की कोशिश में हैं। अभाविप ने दशकों तक वामपंथ प्रेरित हिंसा और अराजकता के विरुद्ध संघर्ष किया है और इनके नापाक इरादों को समाज के सामने उजागर किया है। यह निश्चित है कि इनकी यह कुत्सित चालें कामयाब नहीं हो सकेंगी लेकिन इसके लिये जो भी करणीय होगा, उसे करने के लिये अभाविप आज भी कटिबद्ध है।

वामपंथ प्रेरित वैचारिक असहिष्णुता का ही एक और उदाहरण है सम्मान वापसी का अभियान। हर दिन कोई न कोई लेखक-कलाकार अपना पुरस्कार वापस करता नजर आ रहा है। कई विद्वान तो इसे सरकार को वापस करने के बजाय टीवी स्टूडियो में वापस करने जैसे प्रयासों से घटना में नाटकीय तत्व का समावेश भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का यह एक तरीका है जिसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है। यदि विरोध सच में विरोध के लिये होता तो इसे इतने सस्ते अंदाज में नहीं किया जाना चाहिये था। लेकिन जिस तरह से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वह साबित करता है कि केवल प्रचार पाने और सरकार विरोधी माहौल बनाने का हथकंडा है।

यह जरूर है कि जिस तरह बड़ी संख्या में सम्मान वापसी हो रही है वह यह प्रश्न भी खड़ा करती है कि क्या अब तक केवल एक ही विचारधारा के लोगों को यह खैरात बंट रही थी। और अगर ऐसा था, जो अब साबित भी हो रहा है, तो इस पर भी बहस होनी चाहिये। पुरस्कारों की बंदरबाँट खामोशी से और लौटाने का नाटक सड़कों और स्टूडियो में। दोनों स्थितियां ही अस्वीकार्य हैं और सरकार को कड़े कदम उठाते हुए आगे से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के समुचित प्रयास करने चाहिये।

परिसरों में घटने वाली तमाम घटनाओं के साथ छात्र संसदों की विस्तृत जानकारी भी इस अंक में संकलित करने का प्रयास किया गया है। सामयिक लेख संभवतः आपको विचार करने के लिये प्रेरित करेंगे, यह विश्वास है। दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाओं सहित,

आपका, संपादक

अखिल भारतीय जनजातीय छात्र-युवा संसद : रिपोर्ट

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किये गये छात्र संसद के पहले दिन यानी एक अक्तूबर को अखिल भारतीय जनजातीय युवा संसद कार्यक्रम का प्रस्ताविक भाषण मनरूप मीणा ने दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जनजातीय संस्कृति, समृद्ध संस्कृति के रूप में जानी जाती रही है किन्तु कालान्तर में शिक्षा के स्तर एवं बेरोजगारी से जनजातीय संस्कृति की क्षति हुई है। युवाओं के योगदान से इन क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

उद्घाटन सत्र के द्वितीय वक्ता के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरि बोरीकर ने कहा कि अभाविप विभिन्न रचनात्मक प्रतिभावान छात्र–छात्राओं से युक्त विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अंतरराज्य छात्र–जीवन दर्शन (SEIL), विश्व विद्यार्थी युवा संघ (WOSY) और विकासार्थ विद्यार्थी (SFD) आदि प्रकल्पों द्वारा अभाविप ने निरन्तर देश को जोड़ने तथा पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया है। श्री बोरीकर ने अभाविप की स्थापना के उद्देश्य एवं उसके महत्त्व को भी रेखांकित किया।

सत्र में तृतीय वक्ता के रूप में प्रफुल्ल आकांत ने विषय रखते हुए कहा कि देश के 150 जिले जनजातीय बहुल हैं, इन क्षेत्रों में वन, जल एवं खनिज सम्पदा बड़े पैमाने में उपलब्ध है। जनजातीय समाज ही यहां का मूल समाज है। जनजातीय महापुरुषों को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिये। उन्होनें कहा "जनसंख्या कोई समस्या नहीं, बल्कि एक शक्ति है।" इस पर सकारात्मक दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्राकृतिक दोहन और शोषण के अन्तर को समझने पर बल भी दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मन्त्री जुएल ओराम ने जनजातीय संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्कृति सत्य, परस्पर सहयोग, समन्वय और कर्मठता पर आधारित है। आज जनजातीय समुदाय की बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। उन्होंने जनजातीय संस्कृति, भाषाओं और बोलियों के संरक्षण को रेखांकित किया तथा युवाओं से जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने का भी आह्वान किया।

द्वितीय सत्र का शुभारम्भ आशुतोष मण्डावी के सम्बोधन से हुआ। जिसमें उन्होंने जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास में कौल, किरात, गोण्ड, भील आदि जनजातियों का गौरवपूर्ण उल्लेख किया गया है, किन्तु मुगल काल तथा अंग्रेजों के समय में जनजातीय संस्कृति पर प्रहार किया गया। जैसे छत्तीसगढ की मुढिया जनजातीय और घोटुल युवा प्रथा आदि द्वारा जनजातीय संस्कृति की विकृत छवि को प्रदर्शित किया गया है। इस क्रम में कौल नेगी ने जनजातीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर इस विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने एवं कौशल–विकास, शिक्षण–प्रशिक्षण द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता है। महुआ, ईमली जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में कृषि आधारित व्यवसायिक संस्थाओं तथा हर्बल इंडस्ट्री जैसे उद्योगों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

द्वितीय सत्र में उपस्थित रवि श्रेय ने जनजातीय योजनाओं पर भाषण देते हुए जन–जन तक सरकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया। जनजातीय छात्रवृत्ति योजना, एकल विद्यालय, कोचिंग शिक्षा, आवासीय शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और वन–बन्धु आदि योजनाओं को और अधिक विस्तृत करना वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक है। वहीं, 'जनजातीय संस्कृति एवं परम्परा' विषय पर विचार रखते हुए संजय कुशराम ने

जनजातीय समाज की सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में विवाह व्यवस्था उत्तम थी जैसे गौड समाज में लम्सना विवाह। जनजातीय समाज जल, जंगल, जमीन और जानवर को देवस्वरूप मानता है। वहाँ परम्परागत चिकित्सा गुरबेल, गवाँरपाठा आदि वृक्षों द्वारा होती है।

द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि भीकूजी इदाते ने कहा कि देश से विदेश पर्यन्त विचार करने वाला संगठन अभाविप है। शहरी लोग शिक्षित हैं किन्तु सुसंस्कृत नहीं हैं किन्तु जनजातीय लोग सुसंस्कृत पर शिक्षित नहीं हैं। जनजातीय लोग राष्ट्र के प्रहरी हैं। शहरी समुदाय में संपत्ति अधिक है पर समाधान नहीं, किन्तु जनजातीय समुदाय में समाधान है लेकिन सम्पत्ति नहीं। हमें शोषण एवं दोहन में अन्तर समझना चाहिये।

कार्यक्रम के तृतीय सत्र की शुरुआत युवाओं द्वारा जनजातीय विषयक चर्चा के रूप में हुई। जिसके पश्चात अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के. एन. रघुनन्दन ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग को जनजातीय जीवन को शोध का विषय बनाना चाहिए। उन्होंने जनजातीय समाज की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंग्रेजों के आने के बाद से निरन्तर जनजातीय समुदाय की उपेक्षा होती रही है। आज हमें रोजगार माँगने नहीं सृजन करने के लिए समाज में जाना है। शिक्षा में बदलाव की अनिवार्यता बताते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में जनजातीय समाज के प्रबुद्ध लोगों को अपने आनुभविक सुझाव सरकार को समय–समय पर देने पर बल दिया।

अध्यक्षीय भाषण देते हुए गिरीश प्रभुणे ने शिक्षा व ज्ञान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि रोजगार के लिए डिग्री नहीं ज्ञान होना आवश्यक है। जनजातीय समाज में जो ज्ञान भण्डार है उसको संरक्षित करने के लिए विद्यालय होने चाहिए जिसमें जनजातीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम हो तथा कौशल के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाये।

समापन सत्र में करीब आधे घंटे का समय शून्य काल का चला, जिसके बाद संजय टोप्पो द्वारा जनजातीय विषयक प्रस्ताव पारित किया गया। इस सत्र में मनसुख भाई ने स्वविचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार भी जनजातीय समाज के लिए सही शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने में प्रयासरत है। इसी सन्दर्भ में एकलव्य मॉडर्न स्कूल का उचित क्रियान्वयन तथा वनबन्धु कल्याण योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

समापन सत्र के अन्त में परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने सम्पूर्ण एकदिवसीय जनजातीय छात्र युवा संसद के विषयों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष दिया कि इस देश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना विद्यार्थी परिषद् का कार्य व लक्ष्य है। जनजातीय समाज अकेला नहीं हैं अपितु पूरा परिषद् परिवार उनके साथ है। प्राकृतिक संसाधनों का पेटेंट जनजातीय समाज के पास है अतः जनजातीय लोकसंस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने अभाविप कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को समझाते हुए कहा कि हमें सदैव जनजातीय समुदाय से जुड़े रहना चाहिए। हमें नक्सली विचारधारा की ओर मोड़ने वाले कारणों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना है। देश की विकास यात्रा में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर महिलाओं का समान हिस्सा होना बहुत आवश्यक है। अन्त में युवाओं से भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त किया।

बतादें कि अभाविप द्वारा एनडीएमसी सभागार, दिल्ली में आयोजित 'जनजातीय छात्र युवा संघ युवा संसद' में 19 प्रदेशों के 200 छात्र–छात्रा व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एवीबीपी द्वारा इस प्रकार का यह पहला कार्यक्रम रहा जिसमें देश भर से युवा अपने समाज के विषय में चिंतन करने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए।

अखिल भारतीय छात्रा संसद : रिपोर्ट

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र संसद के दूसरे दिन दो अक्तूबर को अखिल भारतीय छात्रा संसद का आयोजन किया गया। यह संसद अपनी तरह का पहला ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें देश के सभी भागों से तीन सौ से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान उत्साही छात्राओं ने ना सिर्फ महिलाओं के समक्ष पेश आने वाली वर्तमान समस्याओं को रेखांकित किया, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहार्य समाधान लाने के भी प्रयास किये।

एक दिवसीय सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्म निर्भरता और आत्म सम्मान के पांच प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूरे दिन चली इस लम्बी चर्चा को चार सत्रों में विभाजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊपर उल्लिखित विषयों पर समाधान निकालकर संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाना था। ताकि वर्तमान की समस्याओं के निवारणार्थ सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य निश्चित कर सके।

उद्घाटन सत्र का मुख्य भाषण देते हुए अभाविप की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने देशभर से आई छात्राओं को अपने क्षेत्रों में महिलाओं का नेतृत्व करने का आह्वान किया। साथ ही अभाविप के राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभाहगिता निभाने के लिए छात्रों का धन्यवाद भी दिया। इस दौरान परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरि बोरिकर ने दो महापुरुषों महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री को उनकी जयन्ती पर नमम करते हुए छात्राओं को लक्ष्मीबाई की भांति समाज में परिवर्तन लाने के लिए आगे आने का आह्वान किया।

श्री बोरिकर ने कहा कि छात्राओं को स्वयंसिद्धा बनकर स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कार्यक्रम की मुख्य अथिति महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने महिलाओं के कल्याण हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', स्कूल में लिंग चैम्पियन की एक नई अवधारणा की शुरुआत, गांवों में विशेष महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती, ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को 40 लाख रुपये का आवंटन, 'महिला हकदारी' योजना के तहत महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करना आदि योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को आगे बढ़कर अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण हेतु गंभीरता से काम कर रही है, और अपने एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाये हैं। उन्होंने अभाविप द्वारा छात्रा संसद के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्राओं में नेतृत्व का विकास होगा।

दूसरे सत्र में पाँच छात्र नेताओं ने सम्मेलन के पाँच मूल विषयों पर अपने विचार रखे। सुश्री ममता यादव ने कहा कि यह छात्रा संसद भविष्य में मौजूदा राजनीतिक एवं भारत के सामाजिक परिदृश्य में ऐतिहासिक परिवर्तन का द्योतक बनेगा। अंकिता तिवारी ने शिक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रीत करते हुए लैंगिक समानता पर बल दिया। कनिका शेखावत ने महिलाओं की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कठोर उपायों की प्रासंगिकता पर जोर दिया। सुश्री लक्ष्मी ने महिलाओं के बिगड़ते स्वास्थ्य के विषय पर कहा कि कुपोषण, किशोर गर्भावस्था, अनियमित मासिक धर्म और मानसिक दिक्कतों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ्य महिला ही एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव रख सकती है। वहीं, शुभांगी नक्षीणे ने महिलाओं के

आत्मसम्मान विषय पर कहा कि यह जरूरी है कि समाज में कामकाजी महिलाओं और गृहणियों सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। पदि्मनी ने आत्म निर्भरता के महत्व पर अपने विचार रखते हुए जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया।

इस दौरान 'निर्भया की माता जी और निर्भया ज्योति ट्रस्ट की संस्थापक श्रीमती आशा देवी ने भी अपने विचार रख कर सत्र की शोभा बढ़ायी। श्रीमती आशा देवी ने सबसे पहले छात्र समुदाय का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने निर्भया के लिए न्याय की परिवार की माँग का समर्थन किया। भारत में महिलाओं की सुरक्षा की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए आशा देवी ने कहा कि कुछ कानून आज भी सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं। बलात्कार को जघन्य अपराध की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपराधी को सजा जरूर मिले।

सम्मेलन के तृतीय सत्र में अभाविप के विभिन्न राज्यों से आये प्रतिनिधियों ने अपने–अपने राज्य की समस्याओं को सदन में रखा। इस सत्र का समन्वय सुश्री ममता त्रिपाठी ने किया जबकि मुख्य अतिथि अभाविप की वरिष्ट कार्यकत्री सुश्री गीता ताई और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा रहीं। गीता ताई ने कहा कि आज समाज में पुरुषों के आधिपत्य वाले क्षेत्रों में भी महिलाएं अपना परचम फैला रही है। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानते हुए सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करना होगा। इस दौरान, अंजुम चोपड़ा ने अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए लगन, मेहनत के साथ–साथ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा।

चौथे और आखिरी सत्र को खुली चर्चा का रहा, जिसमें अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, गोरक्ष प्रांत के उपाध्यक्ष डॉ उमा श्रीवास्तव, सीडब्ल्यूसी सदस्य सुश्री हरिता और अखिल भारतीय छात्रा प्रभारी सुश्री ममता यादव ने अपने विचार रखे।

अभाविप द्वारा आयोजित छात्रा संसद में देशभर से आयी 300 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान एवं स्वावलम्बन विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान, निर्भया मामले की त्वरित सुनवाई को लेकर एक अपील पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजने को लेकर भी सहमति बनी।

आखिर में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उन्हें उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए मुखर होने की जरूरत है। इसके साथ ही सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ एक जुट होना होगा तभी वो सभी विकारों को परास्त करने में सफल होंगी।

अभाविप का मोबाइल ऐप

डाउनलोड

करने की लिंक आपको

ABVP के

अधिकारिक अकाउंट

http://www.facebook.com/ABVPVOICE

https://twitter.com/abvpcentral

पर और वेबसाइट

www.abvp.org

पर भी उपलब्ध रहेगी।

पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद : रिपोर्ट

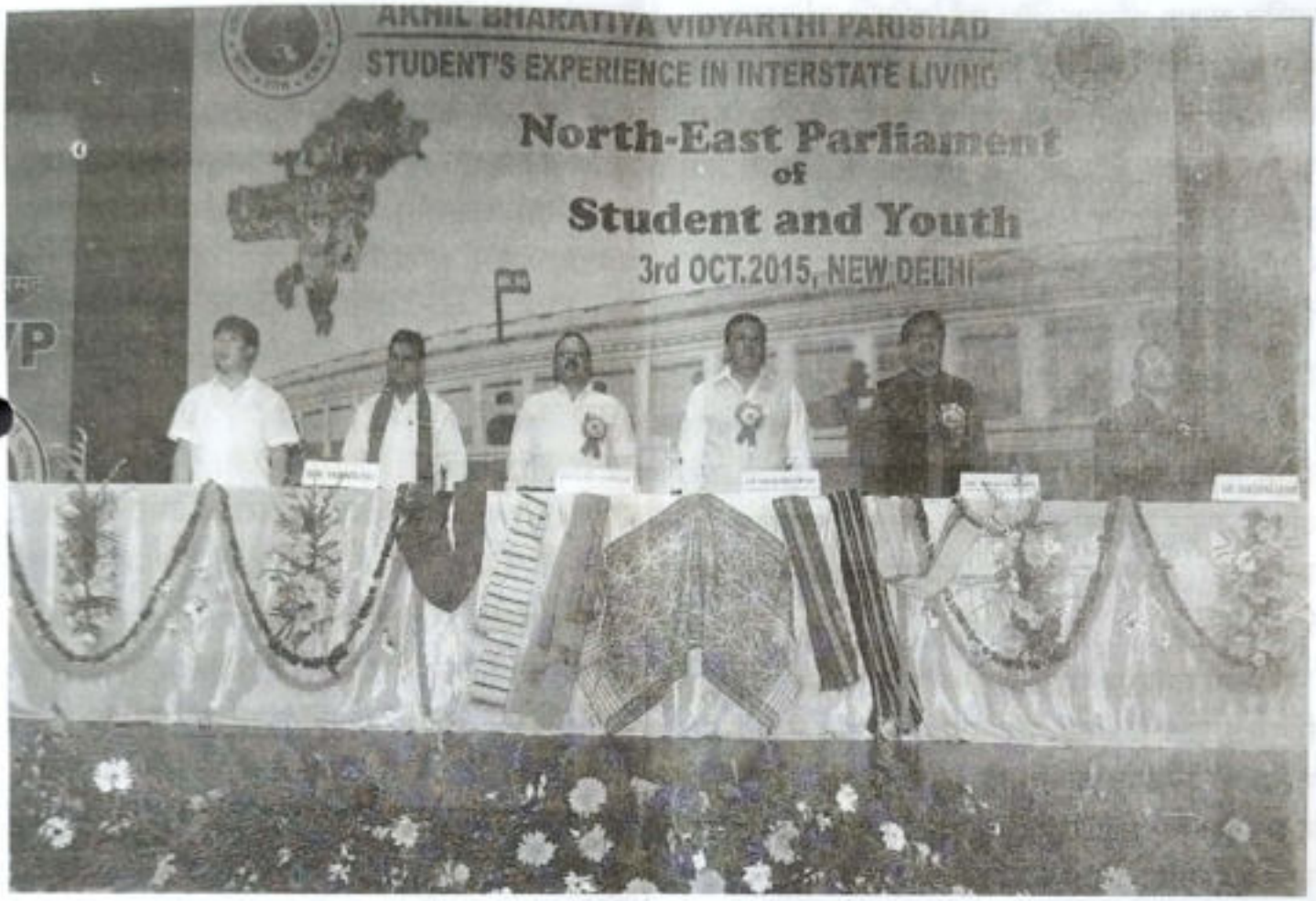

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित छात्र संसद के तीसरे दिन पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अथिति भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मन्त्री सर्बानन्द सोनोवाल रहे। अपने सम्बोधन में श्री सोनोवाल ने युवाओं के महत्त्व को रेखांकित करते हुए उन्हें 'लोकतन्त्र का शक्तिगृह' बताया। 'नेशनल लीडर्स यंग प्रोग्राम' के द्वारा उत्तरपूर्व के युवाओं के कौशल विकास में योगदान को रेखांकित किया। साथ ही, पिछले वर्ष उत्तर–पूर्व के युवाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने के खिलाफ अभाविप के योगदान की सराहना भी की। इस सत्र में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने समस्याओं को गिनाने के स्थान पर उनके निराकरण पर बल दिया। उत्तर–पूर्व में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए उन्होंने प्रशासनिक दुर्वयवस्था को दूर करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में 'उत्तर–पूर्व के विकास के लिए अवसर और समानता' विषय पर चर्चा हुई। जिसमें सत्र के प्रथम वक्ता के तौर पर अतुल कुलकर्णी ने उत्तर–पूर्व के विकास दर का खाका रखते हुए उसे 9.9 फीसदी बताया। इसके अलावा, पर्यटन–उद्योग और अंतर्जलीय परिवहन के साथ वायुपत्तनों के समुचित विकास एवं प्रयोग तथा सड़कों के निर्माण पर जोर दिये जाने की बात कही। दूसरे वक्ता ए. एम. सिंह ने अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता को बल देते हुए शिक्षा के लिए आधारभूत ढाँचा और

उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्राथमिकता दिये जाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने 'विशेष त्वरित सड़क योजना' और पूर्व–पश्चिम गलियारों के महत्त्व को भी रेखांकित किया। सत्र के अंतिम वक्ता रामकरण ने प्राकृतिक सम्पदा के महत्त्व को रेखांकित करते हुए क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास को प्रभावी कार्य बताया। 'अतुल्य भारत' के तहत पर्यटन उद्योग को बढावा देने के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने विचार रखे।

द्वितीय सत्र के बाद प्रश्नोत्तर का दौर चला जिसमें 'डोनर' इत्यादि केन्द्रीय योजनाओं पर विशेष बल दिया गया। प्रश्नोत्तर के जरिए पूर्वोत्तर के छात्रों ने अपने घरेलू समस्याओं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना आदि कमियों को रेखांकित किया।

'सहयोगात्मक एवं शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण' विषयक सत्र में मुख्य वक्ता आर.एन. रवि ने पूर्वोत्तर भारत के इतिहास को बताते हुए वहाँ आंतरिक शांति की स्थापना पर बल दिया। समाधान के लिए उग्रवादी गतिविधियों के लिए उन्होंने औपनिवेशिक शासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लगातार बढ़ते साम्प्रदायिक टकराव, बांग्लादेशी घुसपैठ इत्यादि पर चिंता व्यक्त की। साथ ही पूर्वोत्तर के छात्रों का शेष भारत से जुड़ाव के लिए 'डिजिटल कनेक्टिविटी' की आवश्यकता को भी जरूरी बताया।

इसके अलावा, विचार विमर्श के लिए खुले सत्र में छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रश्न किये, जिसमें अफस्पा, मानवाधिकार, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ, सीमावर्ती क्षेत्रों में व्याप्त तनाव, चकमा व हकोंग जनजाति (अरुणाचल प्रदेश) की समस्याएं प्रमुख रहीं। छात्रों के इस सवालों का युक्तियुक्त जवाब भी आर.एन. रवि ने दिया।

कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजु उपस्थित रहे। सत्र का प्रारम्भ परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने किया। उन्होंने अन्तर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन (सील) के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मध्य संवाद विकसित करने के महत्त्व को रेखांकित किया। 50 वर्षों से सक्रिय 'सील' को उन्होंने 'सांस्कृतिक राजदूत' की संज्ञा दी। इस सन्दर्भ में उन्होंने 'युवा विकास केन्द्र' व 'माई होम इण्डिया' जैसे सांगठनिक प्रयासों की भी सराहना की। जिसके बाद श्रीहरि बोरिकर जी ने 'राष्ट्रीय एकात्मकता' व पूर्वोत्तर भारत के साथ भावनात्मक लगाव के लिए सील के महत्त्व को रेखांकित किया। ततपश्चात, किरण हजारिका जी ने कार्यक्रम के घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

समापन सत्र के मुख्य अथिति किरण रिजिजु ने अपने सम्बोधन में किसी भी देश के विकसित होने के लिए सबसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास को अत्यावश्यक बताया। उन्होंने भारत सरकार के फैसलों को रखते हुए बताया कि प्रत्येक माह पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार केबिनेट मन्त्री या पांच राज्य मन्त्री के प्रवास अनिवार्य है। गृहराज्य मन्त्री ने मोदी सरकार के द्वारा 'लुक ईस्ट' के स्थान पर 'एक्ट ईस्ट' को महत्त्व दिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र का शेष भारत से संवाद को कायम रखते हुए उन्होंने सांस्कृतिक दूरी को मिटाने पर बल दिया।

इससे पहले, पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद कार्यक्रम का प्रारम्भ राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ था। जिसमें शामिल पूर्वोत्तर भारत के 52 छात्र संगठनों का परिचय कराने के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। संसद में प्रतिभाग करने वाले संगठनों में बोडो, मिसिंग, खाती, जैनतिया, गारो, कोच, चकमा, मिजो, ओलो, नोक्टे, न्यीशी, कार्बी, दिमासा, कसारी, राभा, तिवा, मंचू, वांचो, थंसा, सागिन, मोग्का, आदी, छिग्फो सहित अन्य जनजातीय समुदायों के छात्र संगठनों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से थे। ■

जनजातीय छात्र-युवा संसद में जनजातीय शिक्षा आयोग बनाने की उठी मांग

नई दिल्ली। जनजातीय छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा व रोजगार विकसित करने के लिए अब जरूरी हो गया है कि देश में एक सक्रिय व सक्षम जनजातीय शिक्षा आयोग का गठन हो। अभाविप की ओर से राजधानी में आयोजित किए गए जनजातीय छात्र–युवा संसद में इस आयोग की आवश्यकता को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अब इस प्रस्ताव को अभाविप केंद्र व राज्य सरकारों के माध्यम से जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की दिशा में प्रयास करेगी।

अभाविप की ओर से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सभागार में आयोजित छात्र संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केबिनेट मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय छात्रों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और छात्रों से कहा कि वे देश के विकास के लिए काम करें। उन्होंने छात्रों से अपनी भाषाओं को बचाने की अपील की और अपनी संस्कृति, परंपरा व रहन–सहन को बचाकर रखने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। हालांकि, इस मौके पर उन्होंने इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया कि जनजातीय छात्रों को विकास के भरपूर अवसर मिलने चाहिए ताकि वे मुख्यधारा का हिस्सा बन आगे बढ़ सकें। जिससे जनजाति क्षेत्रों में संतुलित विकास संभव हो। उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं की भूमिका बेहद अहम है और आज जरूरत है कि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में तब्दील किया जाए। स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट की बात करते हुए श्री ओराम ने कहा कि यही वह माध्यम है, जिसके जरिये देशी–विदेशी विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान संभव है।

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के लोग काफी 'चालाक' होते हैं और वे आदिवासियों को तुच्छ समझते हैं। ऐसे में समुदाय के प्रति समाज के नजरिए को बदलने की जरूरत है। जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने आपको और अपने आचरण में थोड़े परिवर्तन की जरूरत है ताकि लोगों को हमारी खूबियों का अंदाजा हो सके।

श्री ओराम ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो बात जनजातीय लोग नहीं जानते, वह अन्य समाज के अन्य लोग भी नहीं जानते। जनजातीय युवा खुद को श्रेष्ठ जताने में नहीं लगे रहते और यही एकमात्र उनकी कमजोरी है। जनजातीय मामलों के मंत्री ने कहा कि बड़े शहरों में रह रहे लोगों में यह सामान्य धारणा है कि आदिवासी समान समाज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में सबसे पहले हमें इसी धारणा को दूर करने की जरूरत है। उनके बीच इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि श्आदिवासीश शब्द का क्या अर्थ है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि आदिवासी भी इसी समाज का हिस्सा हैं और वो भी समान आचरण के हकदार हैं।

जुएल ओराम ने कहा कि जनजातीय लोग पिछड़े और उत्पीड़ित हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं। जनजातीयों के पास खनिजों का भंडार है और विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जो अन्य के पास नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोग अपने सरल स्वभाव के कारण ही पिछड़े हैं क्योंकि वो बातों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करने और जोड़–तोड़ के लिहाज से माहिर नहीं हैं, इसी वजह से अन्य लोगों की नजरों में जनजातीय कमतर आंके जाते हैं।

जनजातीय छात्र-युवा संसद में पारित घोषणा पत्र

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् गौरवशाली राष्ट्र के पुनर्निर्माण में छात्रों की भूमिका को सुनिश्चित करते हुए पिछले 66 साल से समाज में सतत कार्यरत है। हम सब जानते हैं की भारत में लगभग 20 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र हैं। देश की जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व जनजातीय समाज का हैं। भारत के इतिहास में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

भारत का जनजातीय क्षेत्र प्रचुर प्राकृतिक संपदा के कारण विशेष महत्व रखता है। ऐसे जनजातीय क्षेत्र की विशेषता को बनाये रखते हुए, जनजातीय क्षेत्र के विकास की गति बढाने और समस्याओं के समाधान के लिए जनजातीय छात्र–युवा संसद अपना घोषणापत्र प्रस्तुत करती है। जिसमें जनजातीय क्षेत्र के सर्वांगींण विकास के लिए शिक्षा, रोजगार और संस्कृति आदि विषयों पर एक साथ विचार करने को आवश्यक ठहराती है।

अभाविप की मांगें-

- जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिक्षण संस्थानों को शुरू किया जाए।
- शिक्षा को लेकर सामाजिक जागरण हो ताकि जनजाति युवा शिक्षा की ओर आकर्षित हों।
- मातृ भाषा में शिक्षा के प्रसार के साथ जनजातीय भाषाओं को सरंक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए।
- बालिका शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाये जायें।
- जनजातीय छात्रों की संख्या के अनुपात में सभी संस्थानों में पर्याप्त छात्रावासों का निर्माण किया जाए।
- जनजातीय समाज से जुड़े विषयों पर अधिक से अधिक अनुसन्धान की व्यवस्था हो।
- जनजातीय छात्रों के लिए नई छात्रवृत्तियाँ शुरू की जाए, उपलब्ध छात्रवृत्तियों की राशि में बढ़ोतरी की जाए।

• जनजातीय छात्रों के लिए नई शोध छात्रवृतियां शुरू की जायें।
• जनजातीय क्षेत्रों में वन–उपज आधारित उद्योग को सरकार बढ़ावा दे जिससे सामाजिक परिवेश भी बदले।
• जनजातीय क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार जनजातीय समाज की निपुणताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति बनाई जाये।
• जनजातीय समाज के लोगों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जाए।
• जनजातीय समाज में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक अलग विभाग का गठन करे।

सामाजिक सशक्तिकरण में जनजातीय परंपरा व संस्कृति की भूमिका –

यह छात्र–युवा संसद जनजातीय परंपरा व संस्कृति के सरंक्षण हेतु इन सुझावों पर समाज व सरकार से जल्द से जल्द कार्य करने की मांग करती हैं कि –
• जनजातीय क्षेत्र की उत्कृष्ट परम्पराओं को समाज के सामने लाया जाए जैसे महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति सम्मान आदि।
•यह संसद संकल्प करती हैं कि वह जनजातीय कला के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में लोक कला महोत्सव का आयोजन करेगी।
• यह संसद देश के युवाओं को आवाहन करती है कि वो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण हेतु आगे आयें।

सरकारी योजनाओं की समीक्षा एवं सुझाव –

यह संसद केंद्रीय व राज्य सम्बंधित समाजोपयोगी योजनाओं के समबन्ध में निम्न सुझावों लागू करने की सरकार से मांग करती हैं :–
• आधुनिक शिक्षा पद्वति के अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान और चिकित्सा पध्दति की शिक्षा दी जाए।
• जनजातीय शिक्षा में सुधार हेतु अलग जनजातीय शिक्षा आयोग का गठन हो।
• राष्ट्रीय स्तर की सरकारी योजनाओं के नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन में जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
• सरकारी योजनाओं की प्रकृति जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने की हो ना कि उन्हें योजनाओं पर निर्भर बनाने की हो।
• छात्रावासों में रहने वाले जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य हेतु छात्र स्वास्थ्य–पत्र शुरू किया जाए।

जनजातीय शिक्षित नहीं पर सुसंस्कृत हैं - भिकू इदाते

नई दिल्ली। जनजातीय युवा संसद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनसीडीएनटी के अध्यक्ष भिकू इदाते ने कहा कि अभाविप देश से विदेश पर्यन्त विचार करने वाला छात्र संगठन है। और इसके बेहतर प्रयास का ही नतीजा है कि जनजातीय समाज के लोगों को अपनी बात रखने का इतना बड़ा मंच मिल सका। जनजातीय संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शहरी लोग शिक्षित जरूर है पर सुसंस्कृत नहीं, जबकि जनजातीय लोग सुसंस्कृत हैं पर शिक्षित नहीं।

एनसीडीएनटी अध्यक्ष ने कहा कि भारत के विभिन्न जिलों में जनजातीय लोगों की संख्या की तुलना में शिक्षा संस्थानों की कमी है जिसके चलते उनके समुचित विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही जनजातीय युवाओं के कौशल विकास को लेकर भी कम प्रयास हुए हैं। फिलहाल वर्तमान सरकार की कोशिशों से लगता है कि यहाँ के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा और वो आगे बढ़ देश के विकास में अपना सक्षम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि देश के समुचित विकास के लिए जरूरी है कि देश का हर कोना अपने स्तर पर विकास के क्रम में योगदान दे। ऐसे में पूर्वोत्तर के लिए जरूरी है कि यहां के युवा अपनी प्रतिभाओं को समझे और सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता के साथ अपना स्वयं का शैक्षिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करें। अगर जनजातीय युवाओं में संस्कार के साथ शिक्षा का भी प्रसार हुआ तो यहां का सामाजिक परिवेश भी बदलेगा और लोगों को जीवन यापन का बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

हर गांव में होगी स्पेशल महिला पुलिस अफसर - मेनका गांधी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय छात्र–युवा संसद के दूसरे दिन छात्रा संसद का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान एवं स्वावलंबन पर देशभर से आई लगभग 300 छात्राओं ने गहन चर्चा की। इस दौरान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गाधी ने कहा कि महिलाओं को पुलिस में 33 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। इस दौरान मेनका गाधी ने यह भी बताया कि हम हर गांव में एक स्पेशल महिला पुलिस अफसर (एसएमपीओ) को नियुक्त करेंगे जो पुलिस और वहां की महिलाओं के बीच पूल की भूमिका अदा करेंगी।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मेनका गाधी ने छात्राओं से आह्वान किया कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ें। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को आगे बढ़कर अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। इस बाबत केंद्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में हमने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने इस बार 1400 महिलाओं को नियुक्ति दी है, ऐसा काम अन्य राज्यों के द्वारा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण होना चाहिए। हर फोन में एक पैनिक बटन विद जीपीएस कनेक्टीविटी होनी चाहिए ताकि आपातकाल में महिलाएं उसका प्रयोग कर सकें। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं।

छात्र संसद में पारित प्रस्ताव

अखिल भारतीय छात्रा संसद की सार्थकता यही है कि समाज में महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान प्राप्त हो सके और वे स्वावलम्बी बन सकें। ऐसे में स्त्रियों के विषय में, उनकी स्थिति, उनके अस्तित्व के विषय में विचार किये जाने तथा स्त्रियों से जुड़े छुए–अनछुए पहलुओं पर भी बात हो सके, इस संसद का उद्देश्य था, ताकि उनका यथासम्भव, यथोचित समाधान ढूंढा जा सके। उन महिलाओं के विषय में विचार किया जा सके जो संसार की आधी जनसंख्या हैं, समाज में जिनकी हर स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस संसद की आवश्यकता इसलिये भी है कि वर्षभर अपने घर–परिवार को समर्पित, विभिन्न प्रकार से शोषित–पीड़ित तथा अपने आप से अनभिज्ञ महिलाओं को इसके द्वारा अपने अधिकार और कर्तव्य की समीक्षा करने का समय मिले और वे इस पर विचार कर सके। चहारदीवारी में बन्द महिला संसार के विभिन्न भागों में महिलाओं द्वारा किये जा रहे शौर्यपूर्ण, प्रशंसनीय कार्यों से परिचित हो सके। वह जान सकें कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, चंदा कोचर, किरण बेदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाओं ने अपने–अपने क्षेत्र में क्या किया और इस समय क्या कर रही हैं? एक सामान्य स्त्री जो पर्दे के पीछे जीवन जी रही है तथा जो मात्र यही जानती है कि 'इतना सा ही है संसार', वह जान सके कि संसार मात्र ड्योढ़ी तक ही सीमित नहीं है अपितु बहुत विस्तृत है। उस स्त्री में जागृति की लहर दौड़ सके तथा वह भी खुली हवा और प्रकाश में जी सके।

1– *शिक्षा*

महिला हित में उठाया गया कोई भी कदम तभी कारगर हो पायेगा जब समस्त महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जायेगी। शिक्षा, मात्र साक्षरता नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा जिससे महिलायें अपने, समाज व राष्ट्र के विषय में निर्णय लेने में सक्षम हो

सकें। आज महिलाओं को ऐसी ही शिक्षा देने की आवश्यकता है, तभी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के साथ–साथ सम्पूर्ण मानवता का सर्वतोमुखी विकास सम्भव होगा। एक महिला के शिक्षित सुसंस्कारित होने से पूरा परिवार संस्कारित होता है। वह परिवार व समाज की नींव है। व्यक्ति से ही समाज बनता है और व्यक्ति के सर्वांग व्यक्तित्त्व का निर्माण करती है नारी। नारी का कार्य पारस पत्थर से भी बढ़कर है क्योंकि पारस मात्र लोहे को सोना बना सकता है। स्त्री एक माँ, बहन, पुत्री व पत्नी के रूप में व्यक्ति तथा समाज का अपने से कहीं अधिक परिष्कार व संस्कार कर सकती है तथा करती भी है। इसीलिये स्त्री का शिक्षित होना समाज के लिये आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश निरन्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्थानों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसमें छात्राओं की सहभागिता भी बड़ रही है। महिला शिक्षा मात्र मिडिल स्कूल और स्नातक स्तर तक ही सीमित नहीं रह गयी है अपितु उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व बढ़ा है। स्वतन्त्रता से पूर्व जहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं क सहभाग 10 प्रतिशत से भी कम था आज वही बढ़कर 41.5 प्रतिशत हो गया है। यह निश्चय ही बहुत स्वागतयोग्य बात है। परन्तु आज भी महिला शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनसे छुटकारा पाकर ही वास्तव में महिला शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

स्वतन्त्रता से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है। सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि ने महिलाओं के संस्थागत शिक्षण हेतु प्रभावकारी प्रयास किये। स्वतन्त्रता के बाद भी समय–समय पर सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं तथा विभिन्न व्यक्तियों के प्रयास महिला शिक्षा को उन्नत बनाने के लिये जारी रहे। आज महिला शिक्षित है, सशक्त है, स्वावलम्बी है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारें भी महिला शिक्षा को बढ़ा देने के लिये अनेक योजनायें संचालित कर रही हैं। परास्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकल बालिका छात्रवृत्ति (Single Girl Child Scholarship) प्रदान की जाती है जो निश्चय ही महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिला शोधार्थियों को पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान की जाती है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र को महिलाओं हेतु सुगम बनाती है। इन विभिन्न योजनाओं का ही परिणाम है कि आज महिला शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगतिगामी परिवर्तन हो रहा है।

महिला शिक्षा को लेकर अभाविप की मांगें–

1. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना स्नातक स्तर पर पढ़ रही बालिकाओं हेतु प्रारम्भ की जाये।

2. सुदूर क्षेत्रों की बालिकाओं को उचित शिक्षा मिल सके इसलिये रानी माँ गाइन्दिल्यू छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की जाय जिसके तहत छात्राओं का चयन करके उन्हें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु भेजा जा सके।

3. शैक्षणिक क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिये शिक्षिका हेतु सावित्रीबाई फुले पुरस्कार एवं छात्रा हेतु भगिनी निवेदिता पुरस्कार केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाये।

4. महिला अध्ययन केन्द्र में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में भारतीय वीरांगनाओं, वीरप्रसूताओं विदुषियों, कवयित्रियों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी महिलाओं एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना सशक्त योगदान करने वाली महिलाओं की स्वाभिमानपूर्ण शौर्यगाथा को स्थान मिले।

5. छात्राओं को शिक्षा हेतु शून्य प्रतिशत ब्याजदर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाय।

6. प्रत्येक शिक्षण संस्थान में महिला विकास प्रकोष्ठ (Women Development Cell) का अनिवार्य रूप से गठन हो एवं सम्यक संचालन हो।

7. यह संसद भारत सरकार से अपील करती है कि शीघ्रातिशीघ्र कस्तूरबा गाँधी छात्रावास जैसे अन्य छात्रावासों को पूर्ण सुरक्षा एवं सुविधा के साथ छात्राओं के रहने योग्य बनाया जाय।

8. जिला स्तर पर छात्राओं के लिये छात्रावास हो।

9. स्नातक स्तर की छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था भी होनी चाहिये।

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बनाये गये छात्रावासों की बदहाल स्थिति में तत्काल सुधार किया जाये और उनकी संख्या भी बढ़ाई जाये।

11. शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु और महिला शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु जिला स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये जिसके माध्यम से छात्राओं को कैरियर चुनने के लिये सही मार्गदर्शन मिले।

12. शिक्षा में नये पाठ्यक्रमों जैसे पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन आदि को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाना चाहिये।

13. व्यावसायिक शिक्षा में छात्राओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिये।

14. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ड्रॉपाआउट रेट कम हो इसके लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

15. विवाह एवं प्रसव के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान से निपटने हेतु विशेष प्रावधान होना चाहिये यथा–पढ़ाई पूरा करने हेतु ऐसे विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिये।

16. कैपिटेशन फीस समाप्त की जाये।

17. सभी शैक्षिक संस्थानों में छात्राओं हेतु सीटें आरक्षित हों।

2- सुरक्षा

महिलायें राष्ट्र की धरोहर हैं, जिन्होंने राष्ट्रहित में हरसम्भव अपना योगदान दिया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया। आजादी के पूर्व से आजादी के उपरान्त तक महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से सम्मानजनक स्थान पर है। परन्तु सदियों से वाह्य आक्रमण तथा बाह्य संस्कृतियों के कुप्रभाव के कारण पनपी अपसंस्कृतियों और समाज में फैली कुरीतियों से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी है। साथ ही इससे महिलाओं को कई सामाजिक बुराईयों एवं कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, सम्पत्ति के अधिकार का अथवा सुरक्षा का महिलाओं को इन सभी क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं पर अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, स्वतन्त्र भारत में महिला सुरक्षा तथा स्वावलम्बन अभी दूर के स्वप्न जैसा है।

सुरक्षा व्यवस्था अर्थात पुलिस और न्याय व्यवस्था की कतिपय नीतियाँ, प्रक्रियायें और न्याय में शिथिलतायें निश्चय ही बलात्कार जैसे जघन्यतम अपराधों के लिये निष्कंटक मार्ग प्रस्तुत करते हैं, जिस पर अपराधी निर्भय विचरण करता है। हमारे कानून व्यवस्था में कई ऐसे छिद्र हैं जिनसे होकर अपराधी सरलतापूर्वक निकल जाता है । कठोर दण्ड का प्रावधानन होने और दण्ड में देरी अपराध को प्रोत्साहन देती है ।

देश का बहुत तेजी से विकास हो रहा है परन्तु महिलाओं के साथ भेदभाव अब भी जारी है। ऐसे में आवश्यकता है कि स्थिति में सुधार हेतु समुचित प्रयास एवं उपाय किये जाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये जिनमें सर्वाधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

चिन्तन और सुधार के विषय

1. बढ़ता लिंगानुपात– सामाजिक कुरीतियों के कारण कन्या का जन्म अभिशाप जैसी मान्यताओं के कारण गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम आज भी अपर्याप्त हैं। समाज में एक बृहद जनजागरण की आवश्यकता है तथा जनसंख्या संतुलन को नैसर्गिक रूप से बनाये रखना अतिआवश्यक है।

2. महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जैसे बलात्कार, अपहरण, दहेज–अपराध, यौन–शोषण, तेजाब फेंकना, छेड़खानी जैसे अपराध आज के समाज पर कलंक हैं। सरकारी कानून तथा उसे लागू करने वाले तन्त्र आज भी अप्रभावी है जिसके कारण महिलाओं का समुचित सहभाग समाज को नहीं मिल पाता है।

3. घरेलू हिंसा– वर्ग, जाति तथा शिक्षा के स्तर से इतर महिलायें समाज में आज भी सुरक्षित नहीं हैं। घर के बाहर के अलावा घर के अन्दर भी महिलाओं के प्रति अपराध होते रहते हैं।

4. कार्यस्थल पर भेदभाव– महिलाओं के साथ अगर वो घर के बाहर कार्य करने वाली हैं तो उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुरुष–प्रधान मानसिकता तथा महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलने को लेकर पुरुषों में पनपी हीन–भावना से अक्सर महिलायें कार्य स्थल पर पुरुषों की ज्यादतियों की शिकार होती हैं। कानून में कार्यस्थल पर महिला की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

महिला सुरक्षा को लेकर मांगें–

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महिला सुरक्षा विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुए कुछ विषयों को प्रकट करती रही है।

• समुचित एवं प्रभावी न्याय व्यवस्था के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 में संशोधन कर कठोर दंड का प्रावधान हो।

• हिंसा की रोकथाम के लिए मानवाधिकार उल्लंघन कानून को प्रभावी बनाना जाये।

• कन्या भ्रूण हत्या नियन्त्रण हेतु लिंग परीक्षण निरोधक कानून एवं लिंग असमानता अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलायी जाये।

• लैंगिक भेदभाव के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए।

• सभी कार्यस्थलों पर जेण्डर सेंसटाइजेशन कार्यक्रमों की नियमित रूप से व्यवस्था हो।

• महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु उन्हें पुरुषों के समान ही महत्त्व दिया जाना चाहिये और उनका आर्थिक शोषण भी नहीं होने चाहिए।

• महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

• ऑनर किलिंग को रोकने के लिये अलग से कानून बनाया जाना चाहिये।

• मजबूरन देह व्यापार के प्रति संवेदनशीलता एवं वैकल्पिक कार्य के अवसर का सृजन किया जाना चाहिए।

• पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रति या महिलाओं से व्यभिचार पर अंकुश लगाया जाना चाहिये।

• दहेज हत्या तथा वधू को जलाना आदि को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिये।

• बाल विवाह निरोधन कानून का सम्यक पालन किया जाना चाहिए।

• सरोगेसी के मामलों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष कानून बनना चाहिये।

• मीडिया व सिनेमा में महिलाओं की चित्रण उपभेग की वस्तु के रूप में ना हो ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए।

• महिला उत्थान हेतु सरकार द्वारा विशेष सरकारी नीतियों के निर्धारन की आवश्यकता है जिससे कि महिला की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकते और वह स्वावलम्बी बन सके।

• महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाये। ■

सबके साथ पूर्वोत्तर का विकास -रिजिजू

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर को कुदरत ने सबकुछ दिया है, लेकिन आज इसे आतंकवाद के लिए पहचाना जाता है। सरकार लगातार यहां माहौल को बेहतर बनाने में जुटी है और हमारी कोशिश है कि पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से मजबूती के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम जारी है और शैक्षणिक मोर्चे पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे है। पूर्वोत्तर का विकास सबके साथ ही संभव है। यह बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) सभागार में आयोजित उत्तर–पूर्व युवा एवं छात्र संसद को संबोधित करते हुए कहीं।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर के विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से व्यापक स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। उत्तर–पूर्व के लोगों के साथ आज दिल्ली में यदि कोई अनुचित घटना घटती है तो उसके खिलाफ पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और ऐसा ना करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को लापरवाही की सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक मोर्चे पर भी देशवासियों के बीच उत्तर–पूर्व राज्यों की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार स्कूली व विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास कर रही है और इसे किताबों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं बनेगा। हमारी सरकार अमल में विश्वास रखती है और अब जरूरत है कि अंतरराज्यीय व्यापार शुरू हो ताकि विकास में तेजी आए। ■

समृद्धि की क्षमता वाला क्षेत्र है पूर्वोत्तर -सोनोवाल

नई दिल्ली। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को हमें समृद्धि की क्षमता वाला क्षेत्र समझना चाहिए ना कि एक पिछड़ा क्षेत्र। पूर्वोत्तर में विकास की असीम संभावनाएं हैं और वर्तमान की केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दे रही है। सोनोवाल ने केन्द्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए सरकार कई योजनाओं को संचालित कर रही हैं। पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। आज आवश्कता है कि पूर्वोत्तर के युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगे, इस हेतु उन्हें उचित अवसर मिलने चाहिए और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अभाविप द्वारा आयोजित इस संसद को संवाद का माध्यम बताया और इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में छात्रों के साथ समस्या हुई तब अभाविप समाधान खोजने दिशा में आगे बढ़ा है। राष्ट्रविरोधी ताकतों के द्वारा छात्रों के बीच भय पैदा किये जाने की स्थिति में भी विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की सहायता की है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि केंद्र सरकार की मदद से पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा, विकास व सुरक्षा के साथ–साथ रोजगार की संभावनाओं को भी विकसित किया जाए। ■

'पूर्वोत्तर को जानो, भारत को जानो'

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने पूर्वोत्तर राज्यों और वहां के निवासियों से शेष भारत में होने वाले भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से 'पूर्वोत्तर को जानो, भारत को जानो' अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत संगठन देशभर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के इतिहास, भूगोल, भाषा, खानपान, वेशभूषा, कला–संस्कृति व जनजातीय जीवन का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरि बोरिकर ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों व युवाओं को आज भी शेष भारत में सहजता के साथ स्वीकार नहीं किया जाता है। राजधानी दिल्ली में ही अक्सर इन राज्यों से आए युवाओं को बेवजह हिंसा व प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। परेशानी की बात ये है कि शेष भारत के लोग इन युवाओं को भारत का नहीं बल्कि चीन, तिब्बत व नेपाल का नागरिक समझने की भूल करते हैं और इससे इनके मन को पीड़ा होती है। संगठन की ओर से शुरू पूर्वोत्तर को जानो, भारत को जानो अभियान का यही उद्देश्य है कि शेष भारत के लोग पूर्वोत्तर राज्यों और वहां रहने वाले करीब पांच करोड़ देशवासियों को करीब से जानें।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा ने बताया कि अभियान के माध्यम से संगठन देश के विभिन्न विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों में पूर्वोत्तर से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को इन राज्यों से अवगत कराएगा। इसमें हम उन्हें ना सिर्फ वहां के खानपान, भाषा, वेशभूषा की जानकारी देंगे बल्कि उनके इतिहास, उनकी मान्यताओं व उपलब्धियों से भी अवगत कराएंगे। इसके लिए पूर्वोत्तर के छात्रों के शेष भारत में प्रवास और शेष भारत के छात्रों के पूर्वोत्तर में प्रवास का भी इंतजाम संगठन की ओर से किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य सीधे तौर पर पूर्वोत्तर को शेष भारत के करीब लाना है ताकि यहां रहने वाले लोगों में भारतीयता व आपसी भाईचारे का भाव पैदा हो सके। ■

पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद में पारित प्रस्ताव

पूर्वोत्तर छात्र युवा संसद के जरिए उत्तर–पूर्व की स्थिति को समझना तथा वहां की विभिन्न समास्याओं को दूर करना ही लक्ष्य है। इसके लिए जरूरी है कि वहां के क्षेत्र शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर आदि की बढ़ोत्तरी हो। साथ ही पूर्वोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़कर भारत के अन्य राज्यों के साथ खड़ा हो सके। इसके लिए सरकार के साथ निजी क्षेत्रों का भी पूर्वोत्तर को बेहतर साथ मिलना जरूरी है।

अभाविप की मांगे–

1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास की दिशा में बेहतर प्रयोग।
2. पूर्वोत्तर में बुनियादी सुविधाओं के साथ क्षेत्र के विकास की कल्पना को पूरा किया जाये।
3. पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाये।
4. असामाजिक तत्वों से पूर्वोत्तर प्रवासियों की सुरक्षा किया जाना चाहिए, जो एक गंभीर चिन्ता का विषय है।
5. रोजगार के अवसरों को सृजित करने की दिशा में काम हो, ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो सके।
6. विश्व स्तर कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास हो।
7. उत्तर पूर्व क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए।
8. उत्तर पूर्व क्षेत्र का अन्य राज्यों से बेहतर संबंध बनाने पर काम होना चाहिए।
9. शासन में जवाबदेही,पारदर्शिता और विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
10. आदिवासी संस्कृतियों, विश्वासों और पहचान को संरक्षित रखते हुए विविधता को बढ़ावा देना होगा।
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र में हानिकारक दवाओं और अन्य व्यसनों के प्रसार कार्य को रोके जाने की जरूरत है।
12. क्षेत्र की अलग–अलग भाषाओं, बोलियों और लिपियों को संरक्षित रखते की जरूरत है। ■

पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्थान के अग्रदूत इम्तियाज अली

वर्ष 2015 का प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार

'प्रो.यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2015' हेतु युवा पुरस्कार 2015 चयन समिति ने इम्तियाज अली (भोपाल, मध्य प्रदेश) का चयन किया है। यह चयन प्लास्टिक ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन कर पर्यावरण संरक्षण एवं कूड़ा बिनने वालों के विकास और उत्थान की परियोजना चलाने को किया गया है। सार्थक संस्था के सचिव एवं परियोजना निदेशक के तौर पर इम्तियाज अली ने ना सिर्फ इलाकों की सफाई का बीड़ा उठाया बल्कि समाज में गन्दगी के कारण बीमारियाँ ना फैलें इसकी भी समुचित व्यवस्था की। ऐसे में इम्तियाज अली देश और समाज के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं।

यह पुरस्कार प्रो. यशवंतराव केलकर, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अभाविप को खड़ा करने तथा उसका विस्तार करने में मील के पत्थर का योगदान दिया, 1991 से प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में दिया जाता है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा विद्यार्थी निधि न्यास की संयुक्त गतिविधि है, जो शिक्षा और छात्रों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न समाजपयोगी काम करने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु समाज के सम्मुख लाना और ऐसे युवाओं के प्रति समूचे युवा वर्ग की कृतज्ञता प्रकट करना एवं अन्य युवाओं में ऐसे काम करने की प्रेरणा उत्पन्न करना यह युवा पुरस्कार का प्रयोजन है। इस पुरस्कार में नगद राशि रू. 50,000/– प्रमाणपत्र एवं स्मृतिचिन्ह समाविष्ट है।

क्षेत्रीय सार्थक सामुदायिक विकास एवं जनकल्याण संस्था, बुद्धिजीवी एवं पर्यावरणविदों का समूह है, जो मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत है। इम्तियाज अली इस सार्थक संस्था के सचिव और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर स्वच्छता एवं सामाज उत्थान की अलख जगाये हुए हैं। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करते हुए स्वच्छता को बनाये रखना है। साथ ही ग्रामीण विकास हेतु लघु उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। कूड़ा बिनने वालों के लिए रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराना। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना एवं सामाजिक समरसता की योजना पर कार्य करना निहित है। इम्तियाज अली का कहना है कि परमश्रद्धेय स्व. नानाजी देशमुख के कथनानुसार वह हर उपेक्षित एवं जरूरतमंदों की मदद को लेकर सार्थक संस्था काम करती है।

सार्थक संस्था ने प्लास्टिक कचरे के निष्पादन की परियोजना को वर्ष 2008 से संचालित कर रही है, जिसमें पर्यावरण विभाग का भी उसे सहयोग मिलता रहा। स्वच्छता के उद्देश्यों के पूरा करने के साथ सार्थक की पहल में प्लास्टिक कचरा बिनने वालों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो यह सुनिश्चित किया गया। इस दौरान, सार्थक के जरिए इम्तियाज अली ने कचरा बिनने वाली महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मुहैया कराये तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की। इन बच्चों को नगर निगम के विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है ताकि यह अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इतना ही नहीं, इन प्लास्टिक कटरों को परिशोधित कर इनका प्रयोग सीमेंट की फैक्ट्रियों एवं अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जा रहा है। वर्तमान में कचरे से भोपाल में ही सात सीमेंट फैक्ट्रियों की भट्टियाँ चल रही हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित होने वाले 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 29 नवम्बर को श्री इम्तियाज अली को 2015 का प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ■

झलकियां ... पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय मंत्री सर्बानन्द सोनोवाल व अभाविप दाधिकारी

प्रतिनिधियों को संबोधित करते संयुक्त खुफिया समिति (जेआईसी) के अध्यक्ष श्री आर. एन. रवि

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजू संबोधन देते हुए

मंच पर उपस्थित केन्द्रीय मंत्री किरण मंत्री किरण रिजिजू व अन्य अतिथि

झलकियां ... छात्र-युवा संसद

डोनर (क्लब्स) मंत्रालय के संयुक्त सचिव ए.एम.सिंह को सम्मानित करते हुए

केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी को सम्मानित करती हुई राष्ट्रीय मंत्री अंजलि चौहान

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू के साथ अभाविप पदाधिकारी व पुर्वोत्तर के छात्र नेता

छात्र संसद में उपस्थित प्रतिनिधि

कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राएं

झलकियां ... जनजातीय छात्र-युवा संसद

उद्घाटन भाषण देते हुए केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम

श्री भीकू जी इदाते (अध्यक्ष, एनसीडीएनटी) को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

प्रतिनिधियों को संबोधित करते राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री के.एन.रघुनंदन

भव्य एवं आकर्षक प्रदर्शनी

कार्यक्रम में मंचासीन केन्द्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओराम व अन्य

झलकियां ... अखिल भारतीय छात्रा संसद

छात्राओं को संबोधित करती महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को स्मृतिचिन्ह प्रदान करते हुए

छात्रा संसद को संबोधित करती हुई सुश्री गीता गुंडे

केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी से प्रश्न पूछती छात्रा प्रतिनिधि

श्रीमती आशा देवी (निर्भया की मां) का स्वागत करती अ.भा.छात्रा प्रमुख ममता यादव

साहित्य, स्वहित के बीच पुरस्कार वापसी पर प्रश्न

✍ अक्षय दुबे 'साथी'

कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य कालचक्र का साक्षी होता है। समाज में अच्छाइयों की रचना और बुराइयों की भर्तसना करते हुए एक लोकतांत्रिक समाज को रचता है। यही कारण है कि साहित्य अर्थात 'सबका हित' की परंपरा के निर्वहन करने वालों अर्थात साहित्यकारों को समाज बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। भारतीय संस्कृति में साहित्यकारों को 'ऋषि' 'सरस्वतीपुत्र' जैसे उपमाओं, पदवियों से अलंकृत करते हुए लोग उनकी शुचिता को प्रणाम करते हैं और उनकी बातों, विचारों को आत्मसात करते हैं।

वाल्मीकि, कालिदास, मीरा, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान की पावन परंपरा और बाबा कबीर के प्रतिरोधों के पद स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की भारतीय रिवायत है, जिसे आम जनता आज भी सम्मान की दृष्टि से देखती है। क्या कबीर से बढ़कर कोई मुखर साहित्यकार हुआ है जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ मारक शब्दों से खुलकर प्रतिरोध किया हो? और बाबा कबीर के दोहे आज भी जनता को मुहजबानी है क्योंकि उनके प्रतिकार की नियत साफ थी कोई सेलेक्टिविजम उनके नियत में नहीं था, ये उनके विचारों की बानगी में खुलकर सामने आती है। लेकिन वर्तमान स्थिति बिल्कुल इसके उलट दिखाई पड़ती है जहाँ सुविधानुसार 'साहित्य' को 'स्वहित' का जरिया बनाकर 'रचनाधर्म" नहीं बल्कि 'विनासकर्म' किया जा रहा है।

आजकल बौखलाए, घिघियाए, छाती पीटते, सर ठोकते, मातम मनाते हुए कुछ खास वर्ग के खास लोगों को एक नयी बीमारी ने अपने गिरफ्त में ले लिया है....बीमारी है पुरस्कार वापसी का। नयी सरकार के आने के बाद इनकी बीमारी में बढ़ोत्तरी तो लाजिमी थी लेकिन गाहे–बगाहे हर कमियों का ठीकरा वर्तमान सरकार पर मढ़ने की प्रवृत्ति केवल और केवल बेजा विरोध की नियत को दिखाती है।

'आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः'(विश्व के कोने–कोने से उत्तम विचार हमारी ओर आते रहे) की वैदिक परिपाटी में चलने वाले हम लोगों को विसम्मति का आदर करना भली–भांति आता है, लेकिन निर्माण के बजाय केवल विध्वंस में विश्वास रखने वाले इन खास बुद्धिजीवियों के द्वारा विरोध के दोहरे मापदंड रखने और विरोध की जद में केवल वर्तमान सरकार को घेरने का प्रायोजन साहित्यिक नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता और अपनी कथित विचारधारा भक्ति समर्पण का कारनामा लगता है। जो कांग्रेस सरकार या राष्ट्रवादी विरोधी सरकारों के सौ–सौ खून माफ कर उनको पाक–साफ होने का क्लीनचिट देती रही है। वहीं, प्रतिरोध के नाम पर पुरस्कार लौटाना तो दूर इसके उलट इस पुरस्कार वापसी की शुरुआत करने वाली लेखिका नैनतारा सहगल 1984 में सिख दंगों के बाद जिन्होंने पुरस्कार लेने में कोई कोताही नहीं बरती। आज एक दो घटना (जबकि यह दुखद घटना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शासित राज्यों में हुई है) के बाद इतनी व्यथित हुई कि विरोध स्वरूप पुरस्कार लौटाने के लिए बाध्य हो गई। धन्य है इनकी राजनीति जो केवल खास वर्ग की पीड़ा को पीड़ा मानती है और किसी पार्टी विशेष की सरकार को दुश्मन.. शायद यही वजह है कि भारतीय जनता की सहिष्णुता अब आक्रोश में परिणित हो रही है।

सत्ता के विरुद्ध साहित्य के जरिये बिगुल फूंकने की संस्कृति बेशक लोकतंत्र में सरकार को बेलगाम होने से रोकती है लेकिन बिलावजह विरोध करना देश की प्रगति में बाधक बनती है। ऐसे में वे विसम्मति के झंडाबरदार नहीं बल्कि देश के लिए अहितकारी बन जाते हैं।

खैर यह मनोदशा पाठकों से कोसों दूर पूर्ववर्ती सरकारों के आयोजनों में मदिरा के साथ जेहन के भीतर उतरती रही है जो अब नई सरकार के आने के बाद दिवास्वप्न भंग होने से खिसीयाहट और झल्लाहट की तरह प्रकट हो रही है....ऐसे बहुतेरे प्रश्न उठ रहे हैं जो इनकी चाल को समझने के लिए काफी हैं..

यह आरोप मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थोप रहा हूँ बल्कि यह आरोप उन मनोदशा वाले विचार समूहों के ऊपर है जिन्हें शाहबानों प्रकरण पर सरकार का कट्टरपंथी ताकतों के आगे समर्पण नहीं दिखाई देता, सिख दंगों के समय की सरकार में जिन्हें सहिष्णुता दिखाई देती है, कश्मीरी पंडितों पर बात भी करना जिन्हें अछूत विषय लगता है, तसलीमा नसरीन को मिलने वाली धमकी के खिलाफ जो कभी इतनी तत्परता नहीं दिखाते उन्हें एकाएक ऐसी कौन सी बीमारी लग जाती है कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। जबकि वे जिन घटनाओं का हवाला दे रहे हैं उन राज्यों की सरकार के खिलाफ भी वे कुछ नहीं बोलते, सारा का सारा प्रायोजित दोष प्रधानमंत्री और राष्ट्रवादी विचारधारा वर्ग पर मढ़ने लगते हैं।

सोचने की बात है इतनी संकीर्ण सोच साहित्यकारों की कैसे हो सकती है? इनके क्रियाकलापों से तो यही लगता है कि इनके पास तयशुदा एकसूत्रीय कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा की बदनामी करना है। बेशक लोकतंत्र में असहमति, प्रतिरोध के लिए एक बड़ा स्थान होना चाहिए और भारतीय गणतंत्र में यह है भी लेकिन कथित साहित्यकारों का एक झुण्ड पुरस्कार वापसी का स्वांग पेश कर क्यों प्रतिरोध की पवित्रता को कमजोर करने में लगा हुआ है? क्यों स्वहित (पुरस्कार वापस कर सस्ती लोकप्रियता) में साहित्य पर सवालिया निशान लगाने पर आमादा हैं? क्या इनके इन कृत्यों की वजह से साहित्यकारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? हो सकता है कि इनकी राजनीति तो सध जाए लेकिन देश की राजनीति की बुनियाद को मजबूत करने की बजाय गफलत फैलाने में लगे हुए इन साहित्यकारों को समयचक्र का साहित्य जरूर नकारेगा, न जाने ये सृजनकर्ता कैसा देश बनाना चाहते हैं?

जब ये तमाम सवाल मेरे इर्द–गिर्द कोहराम मचाते हैं तब मुझे यही लगता है कि ये विरोधी सरकार के नहीं हैं...जनता के भी ये विरोधी नहीं हैं बल्कि ये विरोधी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के हैं और सरकार का विरोध इसलिए क्योंकि वह भारतीय संस्कृति की संरक्षक है। इसी लिए उनके इस वजह से उनका निषेध, प्रतिकार के लिए प्रोपेगेंडा करना प्रतिरोध नहीं गद्दारी कहलाएगी.. अन्तोगत्वा आजकल सोशल मीडिया में एक वाक्य ट्रेंड कर रहा है कि 'काले धन के साथ–साथ काले पुरस्कार भी वापस आ रहे हैं...'

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का नवम्बर 2015 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

"छात्रशक्ति भवन,"
26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली – 110002
फोन : 011–23216298
ई–मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाईट : www.abvp.org

पुरस्कार वापसी पर क्या कहते हैं बुद्धिजीवी

राहुल देव (वरिष्ठ पत्रकार) :– मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार कोई दल नहीं देता बल्कि एक चयन प्रक्रिया के बाद देश के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे में यह पुरस्कार लौटाना उचित नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, ऐसे में विरोध के बजाय संवाद का जरिया बनाने की जरूरत है। जिसके लिए जरूरी है कि पहले हम षड्यंत्रों और असहमतियों को समझें फिर सावधानीपूर्वक कोई कदम उठायें।

मालिनी अवस्थी (प्रख्यात लोक कलाकार) :– साहित्यकारों का आदर इसलिए होता है क्योंकि वे समाज में समरसता घोलते हैं लेकिन आज वही भय का वातावरण बना रहे हैं। कुछ दिन पहले मुन्नवर राणा जी पुरस्कार वापसी के खिलाफ लिखते हैं कि "क्या कलम की स्याही सुख गई है" फिर एकाएक क्या होता है कि मुन्नवर जी नाटकीय ढंग से पुरस्कार वापसी की घोषणा कर देते हैं, क्यों ना हम इसको एक साजिश के तौर पर देखें।

कमलकिशोर गोयनका :– मैं चालीस वर्षों से उस विचारधारा वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वे संवाद के लिए तैयार नहीं हैं, वे स्वयं को श्रेष्ठ विचार वाले बताते हैं। उदय प्रकाश जी छः महीने पहले वक्तव्य देते हैं कि 'अकादमी सम्मान उनके चेहरे में लगे दाग के समान है' उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कुछ लोगों को अपने एनजीओ में घट रहे विदेशी चंदों की फिक्र सता रही है, ऐसे में ये केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश के अलावा कुछ भी नहीं है।

दया प्रकाश सिन्हा (प्रख्यात नाटककार) :– साहित्यकार व्यक्तिगत रूप से कोई विचार रखे तो अलग बात है लेकिन एक साजिश के तहत संगठन बनाकर विरोध करने वाले लोगों को साहित्यकार नहीं बल्कि राजनितिक कार्यकर्ता मानना चाहिए।

अच्युतानंद मिश्र (वरिष्ठ पत्रकार) :– पुरस्कार लौटाने की तात्कालिक उत्तेजना क्या थी यह समझ से परे है। ये जिस चिंतनधारा से निकले हुए लोग हैं उनका अपना इतिहास रहा है। वे महात्मा गाँधी को भी अंग्रेजों का एजेंट कहा करते थे। पुरस्कार लौटाने की तात्कालिक उत्तेजना के रूप में केवल और केवल 2014 का लोकसभा चुनाव दिखाई देता है।

बलदेव वंसी (कवि) :– साठ वर्ष तक जिन शक्तियों के सहारे वे पुरस्कार पाते रहे उनका दबाव है कि वे पुरस्कार वापस करें और उनकी उत्तेजना की बिंदु बिहार चुनाव है। अब हमारा दायित्व बनता है राजनीति का उत्तर प्रबल राजनीति से देना।

नरेन्द्र कोहली (प्रख्यात लेखक) :– कांग्रेस की इंटलेक्चुअल लॉबिंग वामपंथी ही रहे हैं और साठ वर्षों से एक ही विचार पक्ष को पुरस्कृत किया जाता रहा है, और इनका बल एक विशेष प्रकार की असहिष्णुता पर है। वे अन्य प्रकार की असहिष्णुता पर बात नहीं करते लेकिन आज ऐसा क्या बदला कि उन्हें पुरस्कार लौटाने पड़ रहे हैं? दरअसल बदली है केंद्र की सरकार और वे अपने लाभ के लिए एक समुदाय विशेष को डराकर इस देश को दुर्बल बना रहे हैं।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत - अभाविप

छात्र विरोधी नीतियों के लिए सिद्धरमैया सरकार को ठहराया जिम्मेदार

हुबली / बेंगलुरू। कर्नाटक में बेहतर शिक्षा प्रणाली की माँग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बेंगलुरू और हुबली में राज्य स्तरीय रैली निकाली। इस दौरान अभाविप ने बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की मांग करते हुए युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान किये जाने की बात कही। इस रैली में पूरे राज्य के करीब 25 हजार के ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया।

राज्य में शिक्षा व्यवस्था के खराब हालात के लिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महासचिव श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि यह सरकार छात्र विरोधी और किसान विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में चलायी जा रही सभी सरकारी योजनाओं में काफी कमियाँ हैं। एक तो छात्र आधारभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। वहीं, निजी संस्थान शुल्क और डोनेशन के नाम पर छात्रों के अभिभावकों का खून चूसने में लगे हैं। इसके बावजूद सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है।

इसके अलावा, श्रीहरि बोरिकर ने राज्य में लगातार गिरते कानून के स्तर के लिए भी सरकार को दोषी ठहराया। उनका कहना था कि आये दिन महिलाओं और बच्चों के साथ अपराधिक घटनाएं हो रही हैं लेकिन सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। उसे ना तो अपराध दिखायी दे रहे हैं और ना ही वह उनको रोकने के लिए कोई कदम ही उठा रही है। जिसके कारण अपराधी और भी निरंकुश हो गये हैं।

परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव लक्ष्मण ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी शिक्षा प्रणाली पर कार्पोरेट जगत कब्जा जमाने में लगा है। नित नये स्कूल–कॉलेज खोले जा रहे हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना है। ऐसे में शिक्षा का स्तर असाधारण तौर पर गिरता जा रहा है। कार्पोरेट कॉलेजों में सुविधाओं के नाम पर अभिभावकों से पैसे ऐठे जा रहे हैं, और धन के अभाव में गरीब मेधावी बच्चें शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटक में एक भी अच्छा सरकारी कॉलेज नहीं है, सिद्धरमैया सरकार की विफलता को दर्शाता है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार उनकी सरकार ने शिक्षा के नाम पर पैसे का उपयोग किया। सिद्धरमैया सरकार यह भी बतायें कि कितना पैसा शिक्षा का स्तर सुधारने पर खर्च किया गया और कौन सी नयी योजना चलायी गयी जिससे छात्रों को फायदा हो सके।

अभाविप के राष्ट्रीय सचिव विनय बिदारे ने कहा कि शिक्षा के नाम पर हो रहे विभिन्न घोटालों एवं छात्रावासों की खस्ताहाल स्थिति के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार के समझ मांग रखी कि सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढ़ांचों के बेहतर किया जाये।

अभाविप की मांगे

1. सभी सरकारी कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जाये।
2. गरीब मेधावी छात्रों को ध्यान में रखते हुए सीईटी–2006 अधिनियम पर फिर से गौर किया जाये।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति शुल्क की प्रतिशतता में वृद्धि की जाये।
4. प्रो. एम.एम. कुलबर्गी, कुमारी नन्दिता, कुमारी सौजन्या और यल्ला लिंगा की हत्या के मामले की जाँच में तेजी लाई जाये।
5. सभी जिलों में एक सरकारी इंजीनियरिंग और मेडकल कॉलेज होने चाहिए। ■

दिल्ली विश्वविद्यालय में अभाविप छात्रों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभाविप ने परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन और पूरक परीक्षा की मांग को लेकर कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ना करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करने के विरोध में भी परिषद ने आवाज उठायी। परिषद का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन में मांगों पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में विरोध और तेज किया जायेगा।

अभाविप के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा ने कहा कि जब से प्रो. दिनेश सिंह ने प्रभार संभाला है, वह लगातार छात्र विरोधी नीतियाँ चला रहे हैं जिससे छात्रों को नुकसान हो रहा है। बहुगुणा ने कहा कि दिनेश सिंह ने ही विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षाओं और विशेष मौका जैसे प्रारुप को बन्द किया, जिसकी वजह से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध अभाविप प्रो. दिनेश सिंह के छात्र विरोधी नीतियों एवं अन्य भ्रष्टाचार का खुलासा करके रहेगी। अभाविप प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्रो. सिंह ने अपने निजी लाभ के अन्तर्गत एफवाईयूपी परियोजना के तहत लैपटॉप बांटने के लिए 162 करोड़ रुपये खर्च किये। साथ ही इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि जब एफवाईयूपी परियोजना का राष्ट्रीय शिक्षा नीति से स्वीकृति नहीं मिली तो फिर यह विश्वविद्यालय में लागू कैसे हो गया। ऐसे में अगर प्रो. सिंह जाँच में दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सतेन्द्र अवाना ने कहा कि अभाविप यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय के छात्रों को न्याय मिले। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालयों के डेढ़ लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले प्रो. दिनेश सिंह के खिलाफ जाँच बिठायी जाए और दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाये। ■

देश-समाज को अनुशासित और समर्पित युवाओं की जरूरत

पोर्ट ब्लेयर। अनुशासित एवं समर्पित युवा ही समाज और देश के लिए महान कार्य कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं में अच्छे संस्कारों और सदगुणों के भाव भरे जायें। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक के तौर पर तत्पर है। यदि परिषद यूँ ही अपने मार्गदर्शन में युवाओं का पथ प्रदर्शन करती रही तो समाज में हर युवा संस्कारवान होगा। उक्त बातें जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयल के प्राचार्य डॉ.एन. फ्रांसिस जेवियर ने अभाविप द्वारा आयोजित कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहीं।

कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए श्री के. एन. रघुनंदन ने विद्यार्थी समुदाय के मार्गदर्शन एवं उन्नति के लिए विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों और कार्यक्रमों के विविध स्वरूपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही परिषद अपने कार्यों के प्रति समर्पित है। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पोर्ट ब्लेयर के पत्थरगड्डा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में दो दिवसीय कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया था। जिसमें करीब डेढ़ सौ की संख्या में छात्रों में सहभागिता निभाई।

एक ओंकार सतनाम...

✍ आकाश कुमार राय

इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इस बात की पुष्टि सभी धर्मों और उनके पवित्र पुस्तकों में भी होती है और जो इसे मानने वाला ही वास्तव में इंसान कहलाता है। भारत एक धार्मिक देश है और यहां समय–समय पर कई धर्म गुरुओं ने अपनी शिक्षा से मानवता की सेवा करने का संदेश दिया है। ऐसे ही एक धर्म गुरु हैं गुरु नानक देव जी जो सिखों के प्रथम गुरू थे।

सिख धर्म के ग्रन्थों के अनुसार, आज से 546 साल पहले लाहौर (अब पाकिस्तान में) के पास तलवंडी नामक गांव में बैसाख सुदी 3 संवत 1526 यानी 15 अप्रैल 1469 को एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। पिता गांव के पटवारी थे। सिख सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी की सम्पर्ण काव्यमय वाणी गुरु ग्रन्थ साहिब के जपुजी साहिब खण्ड एक के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के आदि गुरु सन्त श्री नानक देव जी की जयन्ती और प्रकाश पर्व मनाया जाता है। इन्होंने लगभग 974 शब्द और 19 राग लिखे हैं। उनके सभी शब्द और राग अनन्त भक्तिमय हैं और निराकार परमेश्वर की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। गुरुवाणी के शुरू में उन्होंने सबसे पहले जो दोहा लिखा है वह इस प्रकार है–

ओम् सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैः।
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरु प्रसादि।।

अर्थात ओमकार रूपी परमेश्वर का एक ही नाम है और यही सत्य है। वह सम्पूर्ण सृष्टि का करता पुरुष है। यह ब्रह्माण्ड उसी परमेश्वर के इशारे पर चल रहा है। वह निर्भय है, उसका किसी से वैर नहीं है। उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई रूप या आकार नहीं है। वह अजन्मा है, अर्थात परमात्मा योनि और जन्म–मरण से रहित है। और उस परमात्मा को पाना गुरु की कृपा पर ही निर्भर करता है।

एक ओंकार सतनाम

नानक बचपन से ही प्रतिदिन संध्या के समय अपने मित्रों के साथ बैठकर सत्संग किया करते थे। उनके प्रिय मित्र भाई मनसुख ने सबसे पहले नानक की वाणियों का संकलन किया था। कहा जाता है कि नानक जब वेईनदी में उतरे, तो तीन दिन बाद प्रभु से साक्षात्कार करने पर ही बाहर निकले। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके पहले शब्द थे– एक ओंकार सतनाम।

बचपन में जब गुरु नानक देव जी स्थानीय पंडित के पास पढ़ाई करने नहीं गए, तो उनके पिता ने उन्हें गाय–भैंसें चराने के लिए जंगल में भेज दिया। जंगल में जाकर गाय–भैंसें चरते–चरते स्थानीय जमीदार राय बुलार के खेतों में घुस गए और थोड़ी ही देर में सारे खेत चट कर गए। राय बुलार को गुस्सा आया और उन्होंने आदमी भेजकर कालू मेहता को बुलवाया। कालू मेहता और नानकी देवी, जो कि उनकी बड़ी बहन थीं, अपने नानक की इस करतूत से बहुत खफा हुए और उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में जाकर देखा कि नानक जी एक मेड के सहारे लेटे हुए ध्यान मग्न हैं और एक काला कोबरा उनके पीछे से आकर फन फैलाए हुए चेहरे पर छाया किए सामने है। जैसे ही कालू मेहता और नानकी वहां पहुंचे सांप अन्तर्ध्यान हो गया। घर वालों को उस दिन पता लगा कि नानक दैवी शक्ति से युक्त कोई अवतारी सन्त हैं।

गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी संसार में अनाचार फैलता है, अवांछित तत्वों से साधारण जन परेशान हो जाते हैं, तब समाज को दिशा देने के लिए किसी न किसी महापुरुष का पदार्पण होता है। उन्हीं महान आत्माओं में से एक थे

गुरु नानक देव। समाज में समानता का नारा देने के लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब ही उसके बच्चे हैं। पिता की निगाह में छोटा–बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और वही हमारा पेट भरने के लिए अन्न भेजता है। इसी प्रकार गुरु नानक भी जात–पात के विरोधी थे। उन्होंने समस्त हिन्दू समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर जाति के कारण यह ऊंच–नीच क्यों? गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम मनुष्य की जाति पूछते हो, लेकिन जब व्यक्ति ईश्वर के दरबार में जाएगा तो वहां जाति नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ उसके कर्म देखे जाएंगे। इसलिए आप सभी जाति की तरफ ध्यान न देकर अपने कर्मों को दूसरों की भलाई में लगाओ।

नानक देव जी अपनी गुरुवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम–नीच न कोई! अर्थात ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। यह तभी हो सकता है, जब व्यक्ति ईश्वर नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है।

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में मुख्यतः तीन बातें हैं। पहला जप यानी प्रभु स्मरण, दूसरा कीरत यानी अपना काम करना और तीसरा जरूरतमंदों की मदद। गुरु नानक की शिक्षा में सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने हमेशा लोगों को प्रेरित किया कि वह अपना काम करते रहे। उनके अनुसार, आध्यात्मिक व्यक्ति होने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को अपना काम–धंधा छोड़ देना चाहिए।

लंगर

गुरु जी ने अपने उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बन सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। इसी कारण जात–पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने के भाव से ही अपने अनुयायियों के बीच लंगर की प्रथा शुरू की थी। जहां सब छोटे–बड़े, अमीर–गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी दुनिया भर के तमाम गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है।

संगत

जातिगत वैमनस्य को खत्म करने के लिए गुरु जी ने संगत परंपरा शुरू की। जहां हर जाति के लोग साथ–साथ जुटते थे, प्रभु आराधना किया करते थे। कथित निम्न जाति के समझे जाने वाले मरदाना को उन्होंने एक अभिन्न अंश की तरह हमेशा अपने साथ रखा और उसे भाई कहकर संबोधित किया। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरु जी ने इस क्रांतिकारी कदमों से एक ऐसे भाईचारे को नींव रखी जिसके लिए धर्म–जाति का भेदभाव बेमानी था।

जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने परिवार के साथ करतापुर बस गए थे। गुरु नानक ने 25 सितंबर, 1539 को अपना शरीर त्यागा। जनश्रुति है कि नानक के निधन के बाद उनकी अस्थियों की जगह मात्र फूल मिले थे. इन फूलों का हिन्दू और मुसलमान अनुयायियों ने अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया।

गुरुनानक देव जी के उपदेश :–

1. ईश्वर एक है। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो।
2. ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है।
3. ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता।
4. ईमानदारी से और मेहनत कर के उदरपूर्ति करनी चाहिए।
5. बुरा कार्य करने के बारे में न सोचें और न किसी को सताएं।
6. सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए।
7. मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरत मंद को भी कुछ देना चाहिए।
8. सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं।
9. भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है पर लोभ–लालच व संग्रहवृत्ति बुरी है।

■

राष्ट्र का करना होगा पुनर्निर्माण - सुनील आंबेकर

वाराणसी। युवाओं को इस बात पर चिन्तन करना चाहिए कि देश का विकास कैसे होगा, कैसे भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। विद्यार्थियों को स्थापित बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने की जगह स्थापित तथ्यों पर प्रश्न उठाना होगा ताकि समाज में बदलाव आ सके। भारत में विकास की पर्याप्त क्षमता है परन्तु उसके उपयोग हेतु हम सब सकारात्मक व आवश्यक प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देश भावना से जुड़कर युवाओं को देश और समाज में अपनी भूमिका पर सोचना होगा। साथ ही युवाओं और उनके अभिभावकों को स्वार्थ के वशीभूत निर्णय लेने के बजाय समाज एवं स्वयं के विकास की चिन्ता करनी चाहिए।

उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आम्बेकर ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो. के. एन. उडुप्पा सभागार में 'राष्ट्र पुनर्निर्माण में छात्रों का योगदान' विषयक व्याख्यान में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से भारतीय चिन्तन दर्शन को अपनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर अभी युवा भारतीय दर्शन की ओर रुझान नहीं दिखायेंगे तो निश्चित ही जिस तरह विश्वभर में भारतीय दर्शन को जानने की होड़ लगी है, मुझे डर है कहीं भारतवासी ही ना इसमें पिछड़ जायें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. अरुणा सिन्हा ने कहा कि युवाओं की भूमिका आज के वक्त में काफी बढ़ गयी है, जिसका उन्हें ध्यान रखना होगा। सिर्फ स्वयं के लिए किये कार्यों से ही युवाओं का योगदान समाप्त नहीं हो जाता। उन्हें तय करना होगा कि स्वयं या व्यक्ति विशेष के लिए किये कार्यों से ज्यादा समाज और देश के बारे में सोचना भी उनका ही काम है। ऐसे में अभाविप के कार्यों की सराहना करते हुए श्रीमती सिन्हा ने कहा कि परिषद लगातार कोशिश करता रहता है कि युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़े रखा जाये ताकि वो देश की परिस्थितियों को भी समझें और अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

इस अवसर पर प्रो. कौशल कुमार मिश्र, अभाविप की महानगर अध्यक्षा डॉ. वन्दना झा, प्रो. के.एन.पी. राजू, प्रो. भीम बली प्रसाद, प्रो. बी.के. सिंह, डॉ. अवधेश सिंह और डॉ. अवधेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

■

बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अभाविप की महारैली

कोलकाता। बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आलम ये है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और इसे ठीक करने की दिशा में सरकार के जो प्रयास हैं, वह भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। उस पर शिक्षण संस्थानों में सत्तारुढ़ दल के छात्र संगठन ने अराजकता फैला रखी है, जिससे शिक्षण सत्र भी प्रभावित हो रहे हैं।

उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्रीहरि बोरिकर ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता पर कटाक्ष करते हुए कहीं। श्री बोरिकर ने कहा कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में सत्तारुढ़ दल के छात्र संगठन ने अराजकता फैला रखी है। अभाविप सदस्यों पर भी अत्याचार किया गया है, पर अब परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब दिया जायेगा।

परिषद के राज्य सचिव सुबीर हलदार ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गयी है और सत्ता के मद में शिक्षा के क्षेत्र को भी नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। जिसके खिलाफ अब अभाविप लामबंद हो गयी है और आवाज उठायेगी। हलदार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद आठ सूत्रीय मांगों का अपना ज्ञापन सरकार को सौंपेगी और मांगों को जल्द माने जाने की भी बात कहेगी। अगर सरकार किसी भी प्रकार आनाकानी करती हैं तो परिषद अपनी रैली को संघर्ष में तब्दील करने को विवश होगी। बतादें कि शिक्षा के क्षेत्र को सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा बदहाल किये जाने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्याराथी परिषद की ओर से एक महाजुलूस निकाला गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने से यह जुलूस धर्मतला के वाई चौनल तक पहुँचा था। जिसमें हजारों की संख्या में अभाविप कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने हिस्सा लिया।

अभाविप की मांगे

- हिंसा व भ्रष्टाचार से मुख्त शिक्षा के लिए टीइटी की निष्पक्ष परीक्षा के जरिए सभी पदों पर शिक्षकों की बहाली करेगा।
- कॉलेजों में पार्टी के एजेंडे को सामने रखते हुए राजनीति बन्द करना।
- कॉलेजों में अध्यापकों से दुर्व्यवहार बंद करना।
- छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- कॉलेजों में भरती के लिए केन्द्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण करना।
- कॉलेज चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन को स्वीकृति देना।
- प्रवेश, वार्षिक परीक्षा एवं परिणाम की अनियमितताओं को रोकने के लिए सभी विश्वविद्यालयों का एक शैक्षणिक कैलेंडर तय करना चाहिए।
- शिक्षा के बुनियादी ढ़ांचे और गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए ताकि छात्रों को राज्य के भीतर ही शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें।
- धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करते हुए सरकार को सभी छात्रों के लिए एक समान अवसर तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए।

नई खिलाफत के खलीफा

✍ अवनीश राजपूत

धार्मिक चेतना कब और क्यों उन्मादी और हिंसक बन जाती है यह प्रश्न सिर्फ आज ही प्रासंगिक है ऐसा नहीं है। यह कल भी प्रासंगिक था और आगे भी बना रह सकता है। देखा जाए तो धार्मिक साम्राज्यवाद ने इस प्रश्न को खुलकर स्वतंत्र मन और आलोचनात्मक भाव से विमर्श के लिए पनपने ही नहीं दिया। धर्म क्या है? इस प्रश्न को इतना ओझल कर दिया गया कि विभिन्न धर्मों में अन्तर्निहित खामियों पर वाद–विवाद धार्मिक सत्तावाद के प्रभाव में दबकर रह गया। अक्सर देखा गया है कि जब ईश्वर के उपासक अपने आपको ईश्वर का दूत मानकर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनका लक्ष्य अपनी आधारभूमि को बढ़ाना हो जाता है। उसके बाद यहीं से विवाद का विमर्श शुरू हो जाता है। ईश्वर की साधना उसकी प्राप्ति और उस तक पहुंचने का मार्ग यदि परिभाषित कर दिया जाता है और उसे अपरिवर्तनीय बना दिया जाता है तो यह कट्टरता की उर्वरा भूमि बन जाती है। एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की मंशा धार्मिक उन्माद को जन्म देती है, जिसके कारण धर्म का मूल तत्व विलुप्त हो जाता है। कैथोलिक और प्रोतेस्टेंन का हिंसात्मक और सत्तावाद को लेकर चलने वाला संघर्ष, इस्लाम और ईसाई के वर्चस्व की लड़ाई और इस्लाम के भीतर शिया–सुन्नी के बीच ईष्या जनित वैमनस्य के अनेक उदाहरण हैं।

आज दुनिया ऐसे ही निषेधात्मक ताकतों का सामना कर रही है। आई.एस.आई.एस. का उभार भी इसी मौलिक सोच का नतीजा है। आई.एस.आई.एस. उस प्रवृत्ति का परिणाम है जो प्रयोगधर्मी मानव के विवेक और स्वतंत्रता की चौकीदारी करता है, अतः आई.एस. आई.एस. से तो बंदूकों से लड़ा जा सकता है परंतु इसकी जड़ में मट्ठा डालने के लिए धर्म के मूल अर्थ को समझने और समझाने की आवश्यकता है। विश्व पटल पर आई.एस.आई.एस. के कारण कई संकट उत्पन्न हो गये हैं जो कि मानवीय सभ्यता और जीवन मूल्यों के लिए अस्तित्व के संकट से कम नहीं है। आई.एस.आई.एस. ने पश्चिम एशिया में इराक और सीरिया के जिन हिस्सों को बल पूर्वक अपने अधीन कर रखा है, वहां एक इस्लामी खिलाफत का विगुल बज चुका है। स्पष्ट है कि इस्लामी खिलाफत की बहाली के लिए चल रहे जिहाद से सभ्य विश्व और विशेषकर भारत पर काफी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इससे पूरे विश्व में भय का माहौल बन रहा है। ऐसे में खिलाफत का अर्थ जो उभरकर आया है उसका सीधा अभिप्राय शरिया की हुकूमत से है। इस्लाम कुबूल करने से इनकार करने वालों, बहुदेव उपासकों और धर्मांतरण से इनकार करने वालों का बेरहमी से कत्ल इनका पेशा है। जबकि आई.एस. आई.एस. की माने तो यह एक वहाबी आन्दोलन है जो इस्लाम के मूल स्वरूप पर विश्वास करता है। उसका मानना है कि इस्लाम की चौदह सौ साल पहले की पीढ़ी के मोहम्मद और उनके साथियों की सोच और तरीके ही सही मायने में इस्लाम है। इसमें किसी तरह का संशोधन करने का मतलब है कि आप इस्लाम के मूल रूप पर विश्वास नहीं करते। उसके अनुसार, यह कुफ्र है और इस्लाम में कुफ्र के लिए एक ही सजा है.. मौत। इस तरह इस्लामिक स्टेट के समर्थक लोगों को इस्लाम की चौदह सौ साल पुरानी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां 'अल्लाह का कानून' शरिया पूरी तरह से लागू होगा। इसके अलावा आई.एस.आई.एस. लोकतंत्र, समाजवाद, फासीवाद सहित कई आधुनिक विचारधाराओं को नकारता है। उसका मानना है कि इस्लाम की पहली पीढ़ी ने जो व्यवस्थाएं तैयार की हैं वे पैगम्बर की बनाई हुई हैं जबकि अन्य व्यवस्थाएं मानव निर्मित हैं। वह इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं को पूरी तरह नकारता है। यही वजह है कि आई.एस.आई.एस. उन इस्लामवादी दलों को भी गुनाहगार मानता है जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सीरिया और इराक में

यजीदियों, शिया मुसलमानों और ईसाइयों पर हो रहे अमानवीय अत्याचार इस बात की स्पष्ट तौर पर पुष्टि करते हैं कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी 'काफिरों' पर ऐसा ही खतरा आने वाला है।

वैसे देखा जाए तो नई इस्लामी खिलाफत की शुरुआत इराक में 1999 में जमायत अल तौहीद वल जिहाद के रूप में हुई थी। बाद में सीरिया में 2004 में इसका नाम बदलकर तंजीम कियादत अल जिहाद फी विलाद अल रफीदान रख दिया गया। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान इस नए संगठन को इराक में अलकायदा का नाम दिया गया। 2006 में इन्होंने मुजाहिद्दीन शुरा काउंसिल का गठन किया। जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अल अनबार और किर कुक सहित छह अन्य इस्लामी उग्रवादी संगठनों को शामिल किया गया। बाद में जब सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ तो इसमें वहां पर सक्रिय इस्लामी उग्रवादी संगठन जैसे अल रका, इदालिब, दिर इज जोर और अलीपो भी शामिल हो गये। अप्रैल 2013 में इन संगठनों ने अलकायदा से अपने सम्बंध विच्छेद कर लिए और एक नये संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लीवेंट की घोषणा कर दी। इसका स्वयंभू खलीफा अली बकर अल बगदादी बना। बगदादी ने दावा किया कि वो इस्लाम का नया खलीफा है और उसका नाम इब्राहिम है। बगदादी ने अमीर उल मोमनीन (दुनीयाभर के मुसलमानों का नेता) की पदवी को भी धारण किया। बाद में इस नए खलीफा ने यह घोषणा की कि उसकी नई खिलाफत का नाम सुन्नी इस्लामिक स्टेट होगा और उसके तहत इराक, शाम, जार्डन, इजरायल, फिलिस्तीन, लेबलान, साइप्रस और तुर्की भी शामिल होंगे। अरबी क्षेत्रों में इस नए संगठन का नाम दाइश घोषित किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार नई खिलाफत उन 81 देशों में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहती है जो कि कभी उस्मानिया साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसमें से 52 देश ऐसे हैं जिनमें इस समय मुस्लिम शासन नहीं है। इन सभी देशों में मुस्लिम शासन की स्थापना इस नए संगठन का लक्ष्य है।

इस्लाम में उग्रवाद और आतंकवाद की पुरानी परम्परा है। ब्रिटेन के सुरक्षा विशेषज्ञ फ्रैंक गॉर्डनर के अनुसार नई उग्रवादी इस्लामी खिलाफत का झंडा काले रंग का है। जो कि कभी हजरत मोहम्मद का झंडा हुआ करता था। इस झंडे पर हजरत मोहम्मद की मोहर अंकित है, जिसमें लिखा है कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर नहीं है। इस तरह की कवायद एक बार फिर नई तरह की खिलाफत का संदेश देने का प्रयास कर रही है और यह साबित करने में लगी है कि इस्लाम के असली उत्तराधिकारी वही हैं। इतना ही नहीं आई.एस.आई.एस. ने खिलाफत के इस मानचित्र में सम्पूर्ण भारत को इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बताया है। नए खलीफा ने ये घोषणा की है कि भारत सहित सभी गैर–मुसलमानों द्वारा शासित देशों का पांच साल के अन्दर सम्पूर्ण इस्लामीकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे इस जेहाद में भाग लें। कुरान और हदीस के अनुसार यह हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि वह खलीफा के आदेश का पालन करें। अगर कोई भी खलीफा के आदेश का पालन नहीं करता है और इस्लाम से विद्रोह करता है तो उसकी सजा मौत है। इसके साथ ही खलीफा ने यह भी घोषणा की है कि भारत में जेहाद की शुरुआत काश्मीर से की जाएगी। इसके बाद सारे हिन्दुस्तान को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदल दिया जाएगा। नई खिलाफत अपने सभी विरोधियों की चाहे वह मुसलमान हो या गैर–मुसलमान निर्मम हत्या कर रही है। निहत्थे, घायलों और आम नागरिकों को भी नहीं बख्सा जा रहा है बकायदा हत्या की वीडियो टेप भी विश्वभर में प्रसारित कर रही है। इस बीच देखा जाए तो काश्मीर में जिहादियों ने इन दिनों नई खिलाफत का विगुल बजाते हुए हाथों में आई.एस. आई.एस. के झंण्डे लिए उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।

मुसलमान शायद आज भी पुरानी इस्लामी परम्परा भूलने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए नई खिलाफत के प्रश्न पर मुस्लिम समाज एक बार फिर विभाजित हो

गया है। अलकायदा के नेता वर्षों से यह कह रहे हैं कि पूरे विश्व के मुसलमान इसीलिए बदहाल हैं क्योंकि उनके हितों की रक्षा करने के लिए आज कोई खिलाफत मौजूद नहीं है। खलीफा का अरबी भाषा में शाब्दिक अर्थ उत्तराधिकारी है। इस्लामी परम्परा के अनुसार खलीफा को हजरत मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि माना गया है। इतना ही नहीं खलीफा के तलवार के नीचे विशुद्ध इस्लामी कानून से शासन चलता था। यह कल्पना भले ही सैद्धान्तिक रुप से सही हो मगर खिलाफत के नाम पर मुसलमानों का जितना खून बहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस्लाम के आधे से अधिक खलीफा स्वाभाविक मौत नहीं मरे हैं या तो उन्हें विष दिया गया या फिर उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी और यह सब इस्लाम में खलीफा पद के दावेदारों ने किया किसी गैर ने नहीं। शायद यही कारण है कि आज भी इसी खूनी इतिहास को दोहराया जा रहा है। ■

'रोजगार परक शिक्षा नीति का हो निर्माण' - श्री रघुनंदन

वाराणसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के. एन. रघुनंदन ने रोजगार परक नई शिक्षा नीति की वकालत की। आर्य महिला पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र–छात्राओं को ज्ञान, योग्यता और रोजगार तीनों मिल सकें। भारतीय परिवेश और संस्कृति के अनुरूप अगर शिक्षा नहीं दी जायेगी तो समाज का वास्तविक विकास नहीं हो सकेगा।

श्री रघुनंदन ने कहा कि वर्तमान में कक्षाओं में भारतीय संस्कृति, कला एवं विचारों का अध्ययन नहीं कराया जाता। ना ही यहाँ भारतीय ज्ञान व परम्परा का पाठ पढ़ाया जाता है जो कि अत्यन्त ही दूर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय होने के साथ भारत की परम्परा और संस्कृति की द्योतक भी होनी चाहिए, और इसी दिशा में भारत की वर्तमान सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है।

व्याख्यान के अन्त में उत्सुक छात्राओं ने श्री रघुनंदन से नई शिक्षा नीति एवं वर्तमान के शैक्षणिक आधार में परिवर्तन, नई शिक्षा नीति की जरूरत एवं बेहतर भविष्य को मजबूत करने की दिशा में उठाये जाने वाले सरकार के कदम के बारे में प्रश्न भी पूछे। जिसके जवाब में के. एन. रघुनंदन ने कहा कि देश का युवा समाज और देश में परिवर्तन की अलख को जगाने का काम तभी कर सकेगा जब उसकी सोच को सही दिशा मिलेगी। ऐसे में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में कमी रही तो यही युवा भ्रमित हो जायेंगे और देश व समाज के विकास की बातें उन्हें समझ नहीं आयेंगी। ऐसे में भारतीय परिदृष्य में बेहतर सोच बनाने के क्रम में नई शिक्षा नीति की जरूरत है, जिसके जरिए युवाओं में सही सोच और विचार फैलाने का काम किया जा सकेगा।

सूर्य की उपासना का महापर्व 'छठ पूजा'

✍ सुनील दुबे

भारतीय संस्कृति में त्यौहार सिर्फ औपचारिक अनुष्ठान मात्र नहीं हैं, बल्कि जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। त्यौहार जहाँ मानवीय जीवन में उमंग लाते हैं वहीं पर्यावरण संबंधी तमाम मुद्दों के प्रति भी किसी ना किसी रूप में जागरूक करते हैं। सूर्य देवता के प्रकाश से सारा विश्व ऊर्जावान है और इनकी पूजा जनमानस को भी क्रियाशील, उर्जावान और जीवंत बनाती है। भारतीय संस्कृति में दीपावली के बाद कार्तिक माह के दूसरे पखवाड़े में पड़ने वाला छठ पर्व मूलतः भगवान सूर्य को समर्पित है। यह त्यौहार इस अवसर पर प्रत्यीक्ष देव भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। आदित्य ह्रदय स्तोत्र से स्तुति करते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये ही भगवान सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, इन्द्र, कुबेर, काल, यम, चन्द्रमा, वरूण हैं तथा पितर आदि भी ये ही हैं।

छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। वैसे भारत में सूर्य पूजा की परम्परा वैदिक काल से ही रही है। सूर्य अर्थात सविता की संचित शक्ति का रूप षष्ठी देवी हैं जिन्हें छठी मइया से संबोधित किया जाता है। सविता की शक्तियाँ ही सावित्री और गायत्री माँ हैं– जिनसे जीवन की सृष्टि और पालन होता है। सावित्री के पश्चात जीवों के पालन हेतु षष्ठी के दिन ही माँ गायत्री प्रकट हुई। विश्वामित्र ऋषि के मुख से गायत्री मंत्र षष्ठी के दिन ही प्रष्फूटित हुआ था।

पर्व के प्रारम्भिक चरण में प्रथम दिन व्रती स्नान कर के सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे 'नहाय खाय' कहा जाता है। वस्तुतः यह व्रत की तैयारी के लिए शरीर और मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। सुबह सूर्य को जल देने के बाद ही कुछ खाया जाता है। लौकी की सब्जी और चने की दाल पारम्परिक भोजन के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरे दिन सरना या लोहण्डा व्रत होता है, जिसमें दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को खीर रोटी और फल लिया जाता है। इस दिन नमक का प्रयोग तक वर्जित होता है। तीसरा दिन छठ पर्व में सबसे महत्व पूर्ण होता है। संध्या अर्घ्य में भोर का शुक्र तारा दिखने के पहले ही निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। दिन भर महिलाएँ घरों में ठेकुआ, पूड़ी और खजूर से पकवान बनाती हैं। इस दौरान पुरूष घाटों की सजावट आदि में जुटते हैं और सूर्यास्त से दो घंटे पूर्व लोग सपरिवार घाट पर जमा हो जाते हैं।

सूर्यदेव जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तो महिलायें पानी में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के लिए सिरकी के सूप या बाँस की डलिया में पकवान, मिठाइयाँ, मौसमी फल, कच्ची हल्दीत, सिंघाड़ा, सूथनी, गन्ना, नारियल इत्यादि रखकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है– 'ऊँ हीं षष्ठी देव्यैम स्वाहा' इसके बाद महिलाएँ घर आकर 5 अथवा 7 गन्ना खड़ा करके उसके पास 13 दीपक जलाती हैं। इसे 'कोसी भरना' कहते हैं। निर्जला व्रत जारी रहता है और रात भर घाट पर भजन–कीर्तन चलता है। छठ पर्व के अन्तिम एवं चौथे दिन सूर्योदय अर्घ्य एवं पारण में सूर्योदय के दो घंटे पहले से ही घाटों पर पूजन आरम्भ हो जाता है। सूर्य की प्रथम लालिमा दिखते ही सूर्यदेव को गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य दिया जाता है एवं इसके बाद सभी लोग एक दूसरे

को बधाई देते हैं। प्रसाद लेने के व्रती लोग व्रत का पारण करते हैं।

सूर्य की कठिन साधना और तप के इस पर्व में दुख और संकट के विनाश के लिए सूर्य का आह्वान किया जाता है। इस पर्व के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा यह है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो दीपावली मनाई गई। जब राम का राज्याभिषेक हुआ, तो राम और सीता ने सूर्य षष्ठी के दिन तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना की। एक प्रसंग यह भी है कि पाण्डवों का वनवास सफलपूर्वक कट जाय इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को षष्ठी देवी के अनुष्ठान करने का परामर्श दिया था। शकुनि के प्रपंच से जब पाण्डवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, तो धौम्य ऋषि ने द्रोपदी से षष्ठी देवी की पूजा करवायी थी।

मूलतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी समाज का पर्व माना जाने वाला छठ अपनी लोक रंजकता के चलते न सिर्फ भारत के तमाम प्रान्तों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है बल्कि मारीशस, नेपाल, त्रिनिडाड, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, हालैण्ड, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय मूल के लोगों द्वारा अपनी छाप छोड़ रहा है। कहते हैं कि यह पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला अकेला ऐसा लोक पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य की भी विधिवत आराधना की जाती है। यही नहीं इस पर्व में न तो कोई पुरोहित होती है और न कोई आडम्बार युक्ती कर्मकाण्ड। छठ पर्व मूलतः महिलाओं का माना जाता है, जिन्हें पारम्पीरिक शब्दावली में 'परबैतिन' कहा जाता है। पर छठ व्रत स्त्री–पुरुष दोनों ही रख सकते हैं।

कष्टों से उबरने की लिए, संतान प्राप्ति के लिए, परिवार के कल्याण के लिए काफी विधि–विधान के साथ छठ मइया की पूजा की जाती है। कठिन उपवास के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को और उगते सूर्य को गंगा में या जैसी सुविधा हो , तालाब, पोखर ,कुंआ, या घर के आँगन में जल या दूध का अर्घ्य देकर और सूप में विभिन्न प्रकार के फलों एवं ठेकुआ का प्रसाद अर्पण कर छठ मइया की पूजा की जाती है। वर्ती का चरण–स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। महिला वर्ती के हाथों से सुहागिन अपने माँगों में सिंदूर भरवाती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।

भारतीय संस्कृति में समाहित पर्व अन्त तः प्रकृति और मानव के बीच तादात्म्य स्थाापित करते हैं। इस दौरान लोक सहकार और मेल का जो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, वह पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को भी कल्याणकारी भावना के तहत आगे बढ़ाता है। यह अनायास ही नहीं है कि छठ के दौरान बनने वाले प्रसाद हेतु मशीनों का प्रयोग वर्जित है और प्रसाद बनाने हेतु आम की सूखी लकड़ियों को जलावन रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि कोयला या गैस का चूल्हात। वस्तुतः छठ पर्व सूर्य की ऊर्जा की महत्ता के साथ–साथ जल और जीवन के संवेदनशील रिश्ते को भी संजोता है।

छठ पर्व की परंपरा में वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिस समय धरती के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है और दक्षिणायन के सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं क्योंकि इस दौरान सूर्य अपनी नीच राशि तुला में होता है। इन दूषित किरणों का सीधा प्रभाव जनसाधारण की आंखों, पेट, स्किन आदि पर पड़ता है। इस पर्व के पालन से सूर्य प्रकाश की इन पराबैंगनी किरणों से जनसाधारण को हानि ना पहुंचे, इस अभिप्राय से सूर्य पूजा का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसके साथ ही घर–परिवार की सुख–समृद्धि और आरोग्यता से भी छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र सहित सभी परिजनों के लिए मंगल कामना से भी जुड़ा हुआ है। सुहागिन स्त्रियां अपने लोक गीतों में छठ मैया से अपने ललना और लल्ला की खैरियत की ख्वाहिश जाहिर करती हैं।

■

'बीफ उत्सव' में परोसा गौमांस, कॉलेज से 6 छात्रों का निलंबन

त्रिशूर। उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर एक व्यक्ति को गौमांस खाने की अफवाह के बाद पीट–पीटकर मार दिए जाने की घटना के खिलाफ केरल के एक प्रमुख सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के परिसर में कथित रूप से 'बीफ उत्सव' आयोजित करने के मामले में संस्थान के छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। श्रीकेरला वर्मा कॉलेज के प्रबंधन के अनुसार संस्थान के नियमों का उल्लंघन करते हुए परिसर में गौमांस परोसने के मामले में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी छात्र स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं।

कॉलेज प्राचार्य सी.एम. लता ने कहा कि कॉलेज परिसर में आधिकारिक समारोहों के दौरान भी मांसाहारी भोजन नहीं परोसा जाता और उन्होंने एसएफआई कार्यकर्ताओं को गौमांस नहीं परोसने की चेतावनी दी थी। कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि हम छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इस मामले में छात्रों को परिसर में गौमांस नहीं परोसने की चेतावनी दी गयी थी। साथ ही, उन्हें सलाह दी गयी थी कि अगर वे ऐसा ही करना चाहते हैं तो कॉलेज परिसर के बाहर ऐसा करें।

इतना ही नहीं आयोजन को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इण्डिया (एसएफआई) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के सदस्यों के बीच झड़प भी हुई। जिसमें पुलिस ने 12 अज्ञात छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। श्रीमती लता ने कहा कि समाचारों के साथ आई तस्वीरों और पुलिस प्राथमिकी के आधार पर छात्रों पर कार्रवाई की गई। कोच्चि राज्य के पूर्ववर्ती महाराजा द्वारा स्थापित केरल वर्मा कॉलेज का प्रबंधन अब कोचीन देवस्वामी बोर्ड देखता है जो राज्य सरकार के तहत स्वायत्त संस्था है।

बतादें कि छात्रों को सस्पेंड करने के विरोध में केरला स्टूडेंट यूनियन ने बीफ फेस्टिवल का आयोजन किया। महाराजा कॉलेज के सेंट्रल सर्किल पर आयोजित इस बीफ फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को बीफ खिलाना था। इसके लिए कैंपस में पका हुआ बीफ ब्रेड के साथ बांटा गया। महाराजा कॉलेज के बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र किशोर के.वी. ने कहा कि किसे क्या खाना है ये लोगों की व्यक्तिगत सोच है। ऐसे में बीफ खाने पर बैन लगाना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है।

इससे पहले, माकपा के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कुछ राज्यों में गौमांस पर प्रतिबंध और उत्तर प्रदेश के दादरी में 50 वर्षीय अखलाक की गौमांस खाने की अफवाह को लेकर हत्या के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए एक अक्तूबर को विद्यार्थियों को कथित रूप से गौमांस और रोटी परोसी थीं। ■

बीफ डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा

नई दिल्ली। दिल्ली के केरल भवन में बीफ (गोमांस) परोसे जाने का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रदर्शन पर रोक से बवाल खड़ा हो गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म महाराष्ट्र में बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले इस धंधे से जुड़े लोगों पर केंद्रित है। जिसके प्रसारण के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से हरी झंडी नहीं दी गई है।

टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पांच छात्रों द्वारा बीफ पर बनाई गई विवादित डाक्यूमेंट्री 'कास्ट ऑन द मैन्यू कार्ड' का प्रदर्शन जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कैम्पस में होने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। जेएनयू प्रशासन द्वारा विवादित डाक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर रोक के बावजूद कैम्पस स्थित साबरमती छात्रावास में डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कार्यक्रम रखा गया, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ सचिव सौरभ वर्मा ने इस विवाद पर कहा कि देश का माहौल वर्तमान में ऐसी फिल्मों के विरूद्ध है। ऐसे में इस फिल्म को जानबूज कर कैम्पस में दिखाने से कैम्पस का माहौल खराब होगा, और इसके दिखाये जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 'कास्ट ऑन द मैन्यू कार्ड' पर रोक के बावजूद वामपंथी छात्र संगठन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। कैम्पस का माहौल बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन ने फिल्म स्क्रीनिंग के लिए लाई गयी प्रोजेक्टर वैन को कैम्पस से बाहर कर दिया। आइसा एवं बापसा छात्र संगठनों ने विवादित डाक्यूमेंट्री को जेएनयू कैम्पस में प्रदर्शित करने की पुरजोर कोशिश की परन्तु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कड़े विरोध के चलते अन्ततः फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो सका।

फिर कामयाब हुआ अभाविप का संघर्ष, नॉन-नेट फेलोशिप नहीं होगी बंद

नई दिल्ली। यूजीसी द्वारा नॉन–नेट फेलोशिप बंद नहीं करने को लेकर चल रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संघर्ष फिर कामयाब हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अभाविप छात्रों की मांगों को मानते हुए नॉन–नेट फेलोशिप को जारी रखे जाने की स्वीकृति दी है। साथ ही स्मृति ईरानी ने इस फेलोशिप को राज्य विश्वविद्यालयों में दिये जाने तथा इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए फेलोशिप को सीधे छात्रों के बैंक खातों में डालने के प्रावधान की भी बात कही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के नेतृत्व में छात्रों का एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मिला था, जिसके बाद श्रीमती ईरानी ने छात्रों की मांगों को सही ठहराया था।

अभाविप दिल्ली प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा ने कहा कि हम माननीय मंत्री स्मृति ईरानी का विद्यार्थियों की मांगे मानने और नॉन–नेट फेलोशिप बहाल करने हेतु हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज तक राज्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के साथ अन्याय हो रहा था। अब उन्हें भी नॉन–नेट फेलोशिप मिलेगी। विद्यार्थियों के अकाउंट में सीधे ट्रांस्फर करने की और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की हमारी मांग भी मान ली गयी है। यह छात्र आन्दोलन की जीत है और हम उन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करते हैं जो इस आन्दोलन में शामिल रहे। भविष्य में भी अभाविप, यूजीसी के इस प्रकार के किसी भी छात्र–विरोधी कदम को नहीं सहेगी।

बतादें कि अभाविप, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू), जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय, बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, एमडीयू रोहतक के छात्र–प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। जिन्होंने अपने ज्ञापन में यूजीसी के छात्र–विरोधी निर्णय को तुरंत रद्द किये जाने और नॉन–नेट फेलोशिप शोध छात्रों को मिले इसकी मांग की थी। ■

छात्र संघ चुनाव में धांधली को लेकर अभाविप ने फूंका प्राचार्य का पुतला

कुमाऊं। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज में अक्टूबर में सम्पन्न हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की अध्यक्ष पद पर जीत के बाद अभाविप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। अभाविप कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर प्राचार्य व चीफ प्रॉक्टर का पुतला फूंका।

अभाविप के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे विकास सिजवाली ने स्थानीय विधायक व मंत्री के इशारे पर छात्रसंघ चुनाव को प्रभावित कराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि छात्रसंघ चुनाव में मतदान के दौरान महिला कॉलेज से मतपेटियां मंगाई गईं और उसी के जरिए चुनाव में धांधली कराई गई। प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में धरना शुरू करने की भी चेतावनी है। इसके साथ ही छात्रसंघ चुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर कोर्ट जाने की भी बात कही है।

प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा अभाविप

मंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंडी में प्रांत अधिवेशन के अंतिम दिन राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि छात्र संगठन का मकसद देशभक्त छात्रों की फौज तैयार करना है। अधिवेशन में आए कार्यकर्ताओं को संगठन के इतिहास व परिषद द्वारा देश में शुरू किए गए प्रकल्पों के बारे में बताया गया। अंतिम दिन प्रदेश का वर्तमान व शैक्षणिक परिदृश्य विषय के दो प्रस्ताव भी रखे गए, जिस पर कार्यकर्ताओं ने सुझाव भी दिए।

अधिवेशन में आने वाले समय में प्रदेश में शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के लिए अभाविप ने अधिवेशन में आदोलन शुरू करने की योजना बनाई। कॉलेजों में मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने के साथ–साथ रूसा के तहत परीक्षा परिणामों को घोषित करने, विश्वविद्यालय द्वारा फीस वृद्धि को वापस लेने और प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मागों को लेकर आदोलन छेड़ने का भी निर्णय लिया गया। अभाविप द्वारा पूरे प्रदेश में संगठन के विस्तार करने की भी योजना बनाई गई है, जिसमें सदस्यता को बढ़ाना सबसे पहला काम रहेगा।

अभाविप ने चलाया सफाई अभियान

शिमला। अभाविप कार्यकर्ताओं ने कोटशेरा महाविद्यालय इकाई में सफाई अभियान चलाया। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का समर्थन करते हुए अभाविप कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान महाविद्यालय की जीवविज्ञान प्रयोगशाला, कैंटीन व महाविद्यालय के सभागार में सफाई की।

अभाविप कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी यह परिश्रम महाविद्यालय को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए है। अभाविप के इकाई सचिव कुलभूषण पंवार ने कहा कि अभाविप युवाओं को प्रेरित करने, अच्छे संस्कार देने व समाज के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। युवाओं को जागरूक करने के लिए यह सफाई अभियान चलाया गया। अभाविप के इकाई अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

फीस वृद्धि के खिलाफ अभाविप ने किया प्रदर्शन

चम्बा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चम्बा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुराग शर्मा ने कहा कि बढ़ी हुई फीस के करण आज आम व गरीब छात्रों को पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

प्रांत सह मंत्री अश्विनी ठाकुर ने बताया कि प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य चिंता का विषय है चाहे वह प्रारंभिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा जो महाविद्यालय में दी जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा में 8वीं तक जो किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी कमी आई है और हिमाचल में रूसा से शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इसके बारे में कोई प्रभावी कदम उठाए। इस मौके पर दीक्षा कुमारी, सचिव गौरव, सह सचिव नीरज, उपाध्यक्ष नितेश, जगेश, बिंदू, बबली, तुलसी, अजय, राजेंद्र, नरेश व सुशील आदि मौजूद रहे।

अभाविप ने उप कुलपति का पुतला फूंका

नरवाना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नरवाना इकाई ने चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के उप–कुलपति द्वारा जींद की लड़कियों के बारे में दिये विवादित बयान के विरोध में विश्वकर्मा चौक पर उनका पुतला फूंककर विरोध जताया।

अभाविप ने वीसी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उप–कुलपति ने अपने बयान में जींद की लड़कियों को देश में बदनाम करने का प्रयास किया है तथा विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी करने पर संगठन चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में जब तक उप–कुलपति जींद के विद्यार्थियों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगा। वहीं, नरवाना ग्रामीण संयोजक हरदीप मोहलखेड़ा द्वारा उप–कुलपति के दिये बयान की निंदा करते हुए कहा कि अब उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विद्यार्थी परिषद शीघ्र ही इस बारे में राज्यपाल से मिलकर उप–कुलपति को उनके पद से हटाने की मांग करेगी। इसके अलावा, जींद में इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन भी चलाया जायेगा।

भुवनेश्वर में होगा अभाविप का 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन

भुवनेश्वर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 61वां राष्ट्रीय अधिवेशन भुवनेश्वर (उड़ीसा) में 26 से 29 नवंबर को आयोजित होना है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा के साथ शिक्षा और देश से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव पारित होंगे। इसके अलावा, उद्घाटन समारोह, प्रास्ताविक, महामंत्री प्रतिवेदन, भाषण, युवा पुरस्कार प्रदान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं समापन समारोह आदि कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्अभाविप की वैचारिक भूमिका एवं दिशाश, श्कार्य पद्धति एवं कार्यकर्ताश, श्अभाविप की आगामी दिशाश इन विषयों पर भाषण एं गटशरू चर्चाओं में इस पर गहराई से चिंतन किया जायेगा। साथ ही 7–8 अगल गटों में महत्वपूर्ण विषयों पर समानांतर सत्र भी चलाये जायेगें।

राष्ट्रीय अधिवेशन 26 नवंबर, 2015 को ध्वजारोहण से प्रारम्भ होकर 29 नवंबर, 2015 को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के साथ सम्पन्न होगी। इस दौरान अलग–अलग विषयों पर सत्र चलेंगे तथा विभिन्न मुद्दों पर कई प्रस्तावों को भी पारित किया जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री का प्रभार भी तय होता है। अधिवेशन के अखिरी दिन प्रो. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

अधिवेशन में अखिल भारतीय स्तर पर देश व प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता अपनी बातों को रखते हुए परिषद के कार्य का विस्तार, उसकी समीक्षा और सुधार को लेकर भी चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखी भी तय की जायेगी।

अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा सभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सभी जिला–विभाग एवं विश्वविद्यालय संयोजक, सभी नगर मंत्री, विश्वविद्यालय परिसर इकाई के अध्यक्ष व मंत्री, देशभर के कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विश्वविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, जनजाति, विकासार्थ विद्यार्थी, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान (थिंक इंडिया) आदि आयामों के भी कुछ कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्राएं सम्मिलित होंगी। ■

OIL INDIA

Creating

OIL & GAS

Assets

for India's Energy Security

Oil India Limited (OIL), India's leading Navratna National Oil & Gas Company with strong Pan-India presence and a share of 9.48% of the country's crude oil production and 6.4% of natural gas production.

OIL's **Mission** is to be *"The fastest growing energy company with global presence providing value to stakeholders."*

OIL has been **Conquering Newer Horizons** with:

Overseas E&P assets and business in Libya, Gabon, Nigeria, Yemen, Venezuala, USA, Mozambique, Myanmar, Bangladesh & Russia.

Foray into Renewable Energy - Wind Energy Plants of installed capacity of 121.6 MW and Solar Power Plant of 5 MW.

International credit ratings - Moody's "BAA2" (higher than sovereign rating) and Fitch Rating "BBB-" (Stable) (equivalent to sovereign rating)

www.chiranjn.com

ऑयल इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Oil India Limited

(A Government of India Enterprise)

Corporate Office : OIL House, Plot Number 19, Sector 16A, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 201301, India
Tel: 0120-2419000, 2419200, Website : www.oil-india.com

RNI No. 32464/78

Bharat Petroleum
energising lives

BPCL introduces

SmartLine

Toll-free 1800 22 4344

Ek Call...Sab Solve

Bharatgas
MAK LUBRICANTS
Speed

At Bharat Petroleum, customers and their convenience are the epicenter of all our business operations. That is why we always develop and deliver various products and services which make things simple for you.

With the same goal, we have now introduced SmartLine - a single window system to listen to all your queries, suggestions and feedback related to any of our offerings.

It will also function as a 24x7 Emergency Helpline to provide immediate assistance. This Toll-Free number is a direct connect between our customers and field teams. So connect with us anytime.

We are just a call away!

www.bharatpetroleum.in